PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 म्यांमार में सैन्य तख्तापलट

भारत पर प्रभाव

बजट स्पेशल 2021-22

2 बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य एवं भारत की विदेश नीति

3 भारत-श्रीलंका संबंध : चुनौतियाँ एवं अवसर

4 अमेरिका की वर्तमान विदेश नीति एवं उसका वैश्विक प्रभाव

5 परमाणु हथियार निषेध संधि : एक अवलोकन

6 पुरानी होती बांध अवसंरचना : एक वैश्विक चुनौती

7 बिग-टेक कंपनियाँ : वैश्विक अविश्वास एवं चुनौतियाँ

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान

प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

फरवरी 2021 | अंक 03

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ. ➢ विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक ➢ क्यू. एच. खान

मुख्य संपादक ➢ कुरबान अली

प्रबंध संपादक ➢ आशुतोष सिंह

संपादक ➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग ➢ प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक ➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी

लेखक ➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी

समीक्षक ➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री

आवरण सज्जा एवं विकास ➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति ➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार

प्रारूपक ➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल

कार्यालय सहायक ➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

- केन्द्रीय बजट 2021–22 की मुख्य बातें — A_1-A_8
- 7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न — 01–14
  - म्यांमार में सैन्य तख्तापलट : भारत पर प्रभाव
  - बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य एवं भारत की विदेश नीति
  - भारत-श्रीलंका संबंध : चुनौतियाँ एवं अवसर
  - अमेरिका की वर्तमान विदेश नीति एवं उसका वैश्विक प्रभाव
  - परमाणु हथियार निषेध संधि : एक अवलोकन
  - पुरानी होती बांध अवसंरचना : एक वैश्विक चुनौती
  - बिग-टेक कंपनियाँ : वैश्विक अविश्वास एवं चुनौतियाँ
- 7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स — 15–21
- 7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) — 22–23
- 7 महत्वपूर्ण खबरें — 24–29
- 7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) — 30
- 7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) — 31
- 7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) — 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

केन्द्रीय बजट 2021-22 की मुख्य बातें

2020-21 अर्थव्यवस्था की स्थिति : एक वृहद दृष्टिकोण

चर्चा का कारण

- केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 15 फरवरी को केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश किया, जो इस नये दशक का पहला बजट है, साथ ही अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है।

वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्ताव जिन 6 स्तंभों पर आधारित हैं वे निम्नलिखित हैं-

- स्वास्थ्य एवं खुशहाली
- भौतिक एवं वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना
- आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
- मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना
- नवाचार और अनुसंधान व विकास
- न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

स्वास्थ्य एवं खुशहाली

- वर्ष 2020-21 के बजट में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस वर्ष के बजट अनुमान में स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए बजट परिव्यय 2,23,846 करोड़ रुपये का है, जबकि इस साल का बजट अनुमान 94,452 करोड रुपये का है, जो 137 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम 'पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' का शुभारंभ किया जाएगा। इससे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित होगी, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान

मजबूत होंगे, और नये संस्थानों का सृजन होगा, जिससे नई और उभरती बीमारियों की पहचान एवं इलाज करने में आसानी होगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। इस योजना के तहत किये जाने वाले **मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं:**

- 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी।
- 11 राज्यों के सभी जिलों और 3382 प्रखंड सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- 602 जिलों और 12 केन्द्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किये जाएंगे।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी), इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत किया जाएगा।
- सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा।
- प्रवेश स्थलों, अर्थात 32 हवाई अड्डों, 11 समुद्री बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग पर 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू किया जाएगा और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत किया जाएगा।
- 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केन्द्रों और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना की जाएगी।
- वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, जैव सुरक्षा स्तर-3 की 9 प्रयोगशालाओं और विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

टीका

- वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
- भारत में तैयार 'न्यूमोकोकल वैक्सीन', जो मौजूदा समय में केवल पाँच राज्यों तक ही सीमित है, को देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य हर वर्ष 50,000 बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाना है।

पोषण

- पोषक तत्वों को बढ़ाने के साथ-साथ इनकी, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर देगी तथा मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करेगी। सरकार सभी 112 जिलों में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाएगी।

जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज और स्वच्छ भारत मिशन

- वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शनों के साथ सभी 4378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन (शहरी) का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। इसे 2,87,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा 2021-2026 तक के 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा। वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने इस बजट में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए 2217 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। पुराने और अनुपयुक्त पाए जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए एक 'स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति' की भी घोषणा की गई। निजी वाहनों के मामले में 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों के मामले में 15 साल बाद स्वचालित फिटनेस केन्द्रों में फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

भौतिक या वास्तविक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना

- **आत्मनिर्भर भारत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर दहाई अंकों में वृद्धि दर हासिल करनी होगी। देश की विनिर्माण कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का अभिन्न अंग बनाने, विशिष्ट क्षमता एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने की जरूरत है। इन सभी को हासिल करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने हेतु 13 सेक्टरों में पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है। इसके लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसकी शुरूआत वित्त वर्ष 2021-22 से होगी। इस पहल से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक उत्पादन स्तर हासिल होगा, वैश्विक दिग्गजों का सृजन होगा और देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा।

वस्त्र

- इसी तरह वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम के अलावा 'मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स (मित्र)' नामक योजना शुरू की जाएगी। इससे 'लगाओ और चलाओ' सुविधाओं से युक्त विश्वस्तरीय अवसंरचना का निर्माण होगा, जिससे निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक दिग्गज अस्तित्व में आएंगे। इसके अतिरिक्त तीन वर्षों में 7 वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएंगे।

अवसंरचना

- वित्त मंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) अपनी तरह की पहली और पूर तरह से सरकारी पहल पर आधारत है। 6,835 परयोजनाओं के साथ एनआईपी क घोषणा क गई थी। इस परयोजना पाइपलाइन का विस्तार कर दिया गया है और अब इसमें 7400 परियोजनाएं हैं। कुछ महत्त्वपूण अवसंरचना मंालय के अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपये तक की लागत क लगभग 217 परयोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना

- बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कों के ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें से 3800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। मार्च 2022 तक सरकार 8500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए भी ठेके दे देगी। इसके साथ ही सरकार 11000 किलोमीटर और लंबे

राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लेगी। सड़क अवसंरचना का और भी अधिक विस्तार करने के लिए कई और आर्थिक कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 लाख करोड़ रुपये का विस्तारित परिव्यय प्रदान किया है, जिसमें से 1,08,230 करोड़ रुपये संबंधित पूंजी के लिए है और जो अब तक का सर्वाधिक है।

रेलवे अवसंरचना

- भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना ख 2030 तैयार की है। इस योजना को वर्ष 2030 तक 'भविष्य के लिए तैयार' रेलवे तंत्र सृजित करना है। घरेलू उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना 'मेक इन इंडिया' को समर्थ बनाने के लिए सरकार की रणनीति का मुख्य बिंदु है। यह संभावना है कि पश्चिमी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर (डीएफसी) और पूर्वी डीएफसी जून, 2022 तक शुरू हो जाएंगे। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं :
- यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किये गये बिस्टाडोम एचएलवी कोच आरंभ किये जाएंगे।
- पिछले कुछ वर्षों में किये गये सुरक्षा उपायों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किये गये नेटवर्क रूटों को स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी, जो मानवीय त्रुटि के कारण होने वाली ट्रेन टकराने की समस्या को समाप्त कर देगी।
- बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए है।

शहरी अवसंरचना

- सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ-साथ सिटी बस सेवा के भी विस्तार के जरिये शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करेगी। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार में आवश्यक सहयोग देने के लिए 18000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी।
- कुल 702 किलोमीटर लंबी मेट्रो परिचालन में है और 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर मेट्रो व आरआरटीएस निर्माणाधीन हैं। टियर-2 शहरों और टियर-1 शहरों के आसपास के इलाकों में कम लागत में समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए दो नई 'मेट्रोलाइट' और 'मेट्रोनियो' लागू की जाएंगी।

विद्युत अवसंरचना

- पिछले छह साल में अतिरिक्त 139 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ बिजली क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं और उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इसके साथ ही 2.8 करोड़ घरों को कनेक्शन दिए जाने के अलावा 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन बिछाई गई हैं।
- वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता को लेकर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए वित्त मंत्री ने 5 वर्ष में 3,05,984 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सुधारों पर आधारित और प्रदर्शन से संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना पेश करने का प्रस्ताव किया है। योजना के तहत, बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को वित्तीय स्थिति में सधार के लिए जरूरी प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और फीडर से अलग करने, प्रणालियों में सुधार सहित अवसंरचना निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग

- बड़े बंदरगाह अपने दम पर अपनी परिचालन सेवाओं के प्रबंधन से एक ऐसा मॉडल बनने की ओर कदम बढ़ाएंगे, जहां एक निजी साझीदार उनकी तरफ से इसका प्रबंधन करेगा। इस उद्देश्य से बजट में वित्त वर्ष 21-22 में निजी सार्वजनिक साझीदारी मॉडल पर बड़े बंदरगाहों 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।
- भारत में वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना का शुभारम्भ किया जाएगा, जिसके तहत मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय नौवहन कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए, 5 वर्ष के दौरान 1,624 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से वैश्विक नौवहन में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के अलावा, भारतीय नाविकों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

- सरकार ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रखी है। इस क्षेत्र की अहमियत को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रमुख पहलों की घोषणा की गयी है:
  - उज्ज्वला योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले ही मिल चुका है और अब 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक इसका विस्तार किया जाएगा।
  - अगले तीन वर्ष में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा।
  - जम्मू व कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
  - गैर भेदभावपूर्ण मुक्त पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में सामान्य वाहक क्षमता की बुकिंग की सुविधा और समन्वय के लिए एक स्वतंत्र गैस वाहक प्रणाली परिचालक की स्थापना की जाएगी।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई में बढ़ोतरी

- सरकार ने बीमा क्षेत्र में स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने और आवश्यक सुरक्षा के साथ विदेशी स्वामित्व एवं नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। नई संरचना के तहत बोर्ड में कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होते हुए ज्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय ही होंगे एवं मुनाफे के एक निश्चित हिस्से को सामान्य आरक्षित निधि के रूप में बरकरार रखा जाएगा।

विनिवेश और रणनीतिक बिक्री

- कोविड-19 के बावजूद, सरकार ने रणनीतिक विनिवेश पर काम जारी रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीईएमएल, पवन

हंस और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों का विनिवेश पूरा कर लिया जाएगा। सरकार का आईडीबीआई बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के दो अन्य बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण भी वर्ष 2021-22 में पूरा करने का प्रस्ताव है।

- सरकार 2021-22 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ भी लाएगी, जिसके लिए आवश्यक संशोधन इसी सत्र में लाया जाएगा।
- एक बेहद अहम घोषणा में वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश पर एक नीति लाने की घोषणा की थी। उनके अनुसार सरकार ने इससे संबंधित नीति को स्वीकृति दे दी है। नीति सभी गैर रणनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा उपलब्ध कराती है। सरकार ने ऐसे चार क्षेत्र चुने हैं जो रणनीतिक हैं, जहां सीपीएसई में न्यूनतम हिस्सेदारी बरकरार रखी जाएगी और बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा। गैर रणनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई का निजीकरण किया जाएगा, अन्यथा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। विनिवेश नीति को गति देने के लिए नीति आयोग ऐसी केन्द्रीय सार्वजनिक कंपनियों की सूची तैयार करेगा, जिनका रणनीतिक विनिवेश किया जाएगा।

आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास

- आकांक्षी भारत के लिए वित्त मंत्री ने समावेशी विकास के अंतर्गत कृषि एवं सहायक क्षेत्रों, किसान कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी मजदूर व श्रम और वित्तीय समावेशन को शामिल करने की घोषणा की है।

कृषि

- वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए एमएसपी व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है, जो सभी कमोडिटीज के लिए लागत की तुलना में कम से कम डेढ़ गुना हो गया है। खरीद एक निश्चित गति से निरंतर बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को भुगतान में भी बढ़ोतरी हुई है।
- 2021 की शुरुआत में, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना की पेशकश की थी। इसके अंतर्गत, गांवों में संपत्ति के मालिकों को बड़ी संख्या में अधिकार दिए जा रहे हैं। अभी तक, 1,241 गांवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं और वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान इसके दायरे में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसी प्रकार, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ बनाए सूक्ष्म सिंचाई कोष को दोगुना कर दिया जाएगा।
- कृषि और सहायक उत्पादों में मूल्य संवर्धन व उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए की गई एक अहम घोषणा के तहत, अब 'ऑपरेशन ग्रीन योजना' के दायरे में अब 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल हो जाएंगे। वर्तमान में यह योजना टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है।
- ई-नैम्स में लगभग 1.68 करोड़ किसान पंजीकृत हैं और इनके माध्यम से 1.14 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ई-नैम को कृषि बाजार में लाया गया है। ई-नैम के साथ 1,000 से ज्यादा मंडियों को जोड़ा जा चुका है। एपीएमसी को अपनी अवसंरचना सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा।

मछली पालन

- वित्त मंत्री ने मछली पकड़ने और मछली उतारने वाले केन्द्रों के विकास में पर्याप्त निवेश का प्रस्तांव रखा। वित्त मंत्री ने कहा कि मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केन्द्रों-कोच्चि, चेन्नई, विशाखापतनम, पारादीप, और पेटुआघाट- को आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रवासी कामगार और श्रमिक

- सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना शुरू की है। उसके बाद में लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन का दावा कर सकते हैं। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रही है। यह संख्या इस योजना के तहत शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या की 86 प्रतिशत है। बाकी चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगले कुछ महीनों में इससे जुड़ जाएंगे।
- सरकार ने चार श्रम कोड लागू करने से 20 साल पहले शुरू हुई प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। वैश्विक रूप से पहली बार सामाजिक सुरक्षा के लाभ वंचित और मंच कामगारों तक पहुंचेंगे। न्यूनतम वेतन सभी श्रेणी के कामगारों पर लागू होंगे और वह सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत आएंगे। महिलाओं को सभी श्रेणियों में तथा उचित सुरक्षा के साथ रात की शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार कर्मचारियों पर एकल पंजीकरण, लाइसेंस प्राप्त करना और ऑनलाइन रिर्टन के साथ अनुपालनभार कम किया जाएगा।

वित्तीय समावेश

- कमजोर वर्गों के लिए किए गए उपायों के अनुपालन में वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत नकदी प्रवाह सहायता को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने मार्जिन मनी की जरूरत 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋणों को भी शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। सरकार ने इस बजट में इसे क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं, जो इस वर्ष के बजट अनुमान से दोगुने से भी अधिक है।

मानव पूंजी को मजबूत बनाना

- वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का अच्छा स्वागत हुआ है। यह कहते हुए कि 15000 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति

के सभी घटकों को शामिल करके गुणवत्ता रूप से मजबूत बनाया जाएगा। उनके अनुसार एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों की भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने एक छत्रक निकाय के रूप में एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है। इसमें मानक, स्थापना,मान्यता, विनियमन और वित्त पोषण के लिए 4 अलग घटक शामिल हैं। लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए सरकार ने लेह में केंद्रीय विश्व विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण

- सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे प्रत्येक स्कूल की लागत 20 करोड़ से बढ़ाकर 38 करोड़ तथा पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में 48 करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जानजातियों के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय सहायता बढ़ाई गई थी और 2025-26 तक छह वर्षों के लिए कुल 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों को लाभ मिलेगा।

कौशल

- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ भागीदारी में कौशल योग्यता, आकलन और प्रमाणीकरण के साथ-साथ प्रमाणीकृत कर्मियों की तैनाती के निर्धारण के लिए एक पहल प्रक्रियाधीन है। जापानी औद्योगिक और व्यावसायिक कौशल तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण में सहायता के लिए जापान और भारत में एक सहयोगात्मक ट्रेनिंगइंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम (टीआईटीपी) भी चल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक देशों के साथ ऐसी पहल की जाएगी।

नावाचार, अनुसंधान एवं विकास

- वित्तमंत्री ने कहा कि जुलाई 2019 की अपने बजट भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की घोषणा की थी उन्होंने कहा कि पांच वर्षों के लिए एनआरएफ का परिव्यय 50 हजार करोड़ रुपए होगा। इससे पहचान किए गए राष्ट्रीय प्राथमिकता की जरूरत वाले क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए देश में समग्र अनुसंधान इको सिस्टम को मजबूत बनाना सुनिश्चित होगा। सरकार एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) की शुरुआत करेगी। इससे प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई शासन एवं नीति संबंधित जानकारी दौलत इंटरनेट पर उपलब्ध होगी।
- अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) कुछ छोटे भारतीय उपग्रहों के साथ ब्राजील से एमेजोनिया उपग्रह ले जाने वाले पीएसएलवी-सीएस को लॉन्च करेगा।
- गंगायन मिशन गतिविधियों के एक भाग के रूप में चार भारतीय अंतरिक्ष यात्री रूस के जैनेरिक स्पेस फ्लाइट आस्पेक्ट पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पहला मानव रहित प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में होगा।

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

- वित्त मंत्री ने बजट के छः महत्वपूर्ण स्तम्भों पर जोर देते हुए न्याय को तेजी से उपलब्ध कराने के लिए पिछले कुछ वर्षों में अधि करणों में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने अधिकरणें के कामकाज को युक्तिपूर्ण बनाने के लिए आगे उपाय करने का भी प्रस्ताव किया। सरकार ने 56 संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों का पारदर्शी और कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ संसद में राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर विधेयक पेश किया है। उन्होंने यह घोषणा भी की कि भारत के इतिहास में आगामी जनगणना प्रथम डिजिटल जनगणना हो सकती है और इस बड़े और महत्वपूर्ण कार्य के लिए वर्ष 2021-2022 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- वित्त मंत्री ने कहा संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 9.5 प्रतिशत हो गया है और इसे सरकारी ऋणों, बहुपक्षीय ऋणों, लघु बचत निधियों और अल्पकालिक ऋणों के माध्यम से धन उपलब्ध कराया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार सरकार को अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। बजट अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- सरकार की योजना राजकोषीय समेकन के मार्ग पर लगातार चलने की है और राजकोषीय घाटा स्तर को कम करके 2025-26 तक इस अवधि के दौरान साधारण रूप से स्थिर ह्रास के साथ जीडीपी के 4.5 प्रतिशत स्तर पर लाना चाहते हैं। सरकार पहले बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व में ऊछाल लाकर दूसरे परिसंपत्तियों,जिनमें लोक उद्यम और भूमि सम्मिलित हैं,के मुद्रीकरण से प्राप्तियां बढ़ाकर समेकन हासिल करने की उम्मीद करती है।
- 15वें वित्त आयोग की मद के अनुसार सरकार राज्यों के लिए निवल उधार की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत पर नियत करने की अनुमति दे रही है।

- 9 दिसंबर, 2020 को 15वें वित्त आयोग ने 2021-2026 की अवधि को कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा 41 प्रतिशत पर बरकरार रखते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संसद में रख दी है। आयोग की सिफारिश पर बजट में 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न को भरने में वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए आयकर प्रक्रियाओं के समय-सीमा में कमी, विवाद समाधान समिति के गठन की घोषणा, फेसलेस आईटीएटी, एनआरआई को छूट, लेखा परीक्षा छूट की सीमा में वृद्धि और लाभांश आय के लिए भी राहत प्रदान की है। उन्होंने देश में बुनियादी ढांचे में विदेशी निवेश को आकर्षित करने, सस्ते और किराए के आवासों के लिए राहत, आईएफएससी के लिए कर प्रोत्साहन, छोटे चौरिटेबिल ट्रस्टों को राहत और स्टार्ट-अप्स के लिए प्रोत्साहन जैसे कदमों की भी घोषणा की।
- वित्त मंत्री के अनुसार महामारी के बाद, दुनिया एक नये रूप में उभरती हुई नजर आ रही है और भारत इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिदृश्य में हमारी कर प्रणाली को पारदर्शी एवं कुशल होना होगा और देश में निवेश एवं रोजगार को प्रोत्साहन देना होगा। इसके साथ-साथ कर दाताओं पर न्यूनतम बोझ डालना होगा। इसके अनुसार कॉरपोरेट कर दर में कमी, लाभांश वितरण कर की समाप्ति और छोटे करदाताओं के लिए छूट में वृद्धि सहित करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए सरकार द्वारा सुधारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई थी। उनके अनुसार वर्ष 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 6.48 करोड़ रही, जबकि 2014 में यह संख्या 3.31 करोड़ थी।
- बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा राहत प्रदान की गई है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें पेंशन और ब्याज सहित आय प्राप्त होती है, उन्हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। उन्हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा। स्वदेश लौटने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए आयकर से जुड़े कठिन प्रावधानों को सरल बनाने और विदेश से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए सरल नियमों का प्रावधान बजट में किया गया है। इनके अनुसार टीडीएस मुक्त लाभांश भुगतान आरईआईटी/आईएनवीआईटी को करने का प्रस्ताव किया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि दर पर लाभांश आय में कर कटौती का प्रस्ताव किया गया है। बजट में यह भी प्रावधान है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश का भुगतान या उसकी घोषणा के बाद ही उत्पन्न होती है। उनके अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि शेयर धारकों द्वारा अग्रिम कर भुगतान करने के लिए लाभांश आय की सही गणना नहीं की जा सकती।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा। सरकार द्वारा लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने सस्ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय-सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए किराये के सस्ते मकान उपलब्ध कराने के प्रावधान में वित्त मंत्री ने सस्ते किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा की है।
- देश में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए श्रीमती सीतारमण ने स्टार्ट-अप्स के लिए कर छूट का दावा करने की समय-सीमा एक वर्ष और 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। इस आदेश के अनुसार स्टार्ट-अप्स के लिए संदर्भित कोष में निवेश की पूंजी पर नियम आधारित छूट को प्राप्त करने के लिए समय-सीमा एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दी गई है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न कल्याण निधियों में नियोक्ताओं का अंशदान जमा करने में हुई देरी के कारण कर्मचारियों को ब्याज/आय की स्थायी हानि होती है। नियोक्ता द्वारा इन निधियों में कर्मचारी का अंशदान समय पर जमा करने के लिए वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि कर्मचारी का अंशदान देरी से जमा करने के बारे में नियोक्ता को कभी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इस वर्ष का बजट अनुपालन का भार कम करने के लिए आयकर कार्यवाही मौजूदा छह साल से तीन साल करने के लिए समय-सीमा में कटौती का प्रावधान करता है। कर प्रवंचना के गंभीर मामलों में जहां एक वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक की आय को छुपाने के सबूत मिलते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित आकलन को 10 वर्ष तक दोबारा खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुख्य आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
- कराधान प्रणाली में वाद कम करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए संकल्प का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित प्रत्यक्ष कर 'विवाद से विश्वास'योजना को अच्छी तरह अपनाया गया है। 30 जनवरी, 2021 तक 1 लाख 10 हजार से अधिक करदाताओं ने इस योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर विवाद को निपटाने का विकल्प चुना है। छोटे करदाताओं के वाद और कम करने के लिए श्रीमती सीतारमण ने एक विवाद समाधान समिति स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अनुसार 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपये तक की विवादग्रस्त आय के साथ कोई भी व्यक्ति इस समिति में पहुंचने के लिए हकदार होगा और उसे दक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समिति के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की।
- डिजिटल लेन-देन करने को प्रोत्साहन देने और ज्यादातर लेन-देन को डिजिटल माध्यम से करने वाले व्यक्ति पर अनुपालन का भार कम करने के लिए बजट में कर लेखापरीक्षा की सीमा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इससे ऐसे व्यक्ति लाभान्वित होंगे जो 5 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का 95 प्रतिशत लेन-देन डिजिटल माध्यम से करते हैं।
- विनिर्माण के क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बजट में निजी

निधि के व्यय से जुड़ी स्थितियों, वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रतिबंधों और विनिर्माण में सीधे निवेश से जुड़े नियमों को सरल बनाकर राहत प्रदान की गई है। आदेश के अनुसार विनिर्माण के लिए कोष इकट्ठा करने में जीरो कूपन बॉन्ड शुरू किया जाएगा। बजट में कर के तौर पर एक सक्षम जीरो कूपन बॉन्ड जारी करके धन जुटाने के तहत अधिसूचित बुनियादी ऋण निधि के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के मुद्दे पर, वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में रिकार्ड जीएसटी संग्रह किया गया है। उनके अनुसार जीएसटी को भविष्य में और सरल बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। जीएसटी प्रणाली की क्षमता भी बढ़ा दी गई है। विशेष अभियान चलाकर कर वंचकों और जाली बिल निर्माताओं की पहचान करने के लिए गहन विश्लेषण और कृत्रिम आसूचना का भी उपयोग किया गया है।
- सीमा-शुल्क नीति के संबंध में, वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल करने और अधिक निर्यात को सहायता देने के लिए सीमा-शुल्क नीति के दो उद्देश्य हैं। उन्होंने कहा कि अब कच्ची सामाग्रियों की सुलभता तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने इस वर्ष 400 से अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार व्यापक रूप से परामर्श करेगी और 1 अक्टूबर, 2021 से विकृतियों से मुक्त संशोधित सीमा-शुल्क संरचना स्थापित की जाएगी। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अब से सीमा-शुल्क में कोई नई रियायत इसके जारी होने की तिथि से दो वर्षों के बाद 31 मार्च तक वैध होगी।
- वित्त मंत्री ने वृहत्तर घरेलू मूल्यवर्धन के लिए, चार्जरों के कल-पुर्जों और मोबाइल के सब-पार्टस से कुछ रियायतें वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मोबाइल के कल पूर्जे शून्य दर से साधारण 2.5 प्रतिशत की दर में परिवर्तित होंगे। उन्होंने गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलैस स्टील उत्पादों पर सीमा-शुल्क एक समान रूप से 7.5 प्रतिशत कम करने की घोषणा की।
- कच्चे माल की आवकों से मनुष्य-निर्मित टैक्सटाइल पर युक्तिसंगत शुल्क की आवश्यकता पर जोर देते हुए, वित्त मंत्री ने नायलॉन श्रृंखला को पॉलीस्टर और मानव-निर्मित अन्य रेशों के बराबर लाने के साथ-साथ कैप्रोलैक्टम. नायलॉन चिप्स और नायलॉन फाइबर तथा धागे पर बीसीडी दरों को एकसमान रूप से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा की। उनके अनुसार इससे टैक्सटाइल उद्योग, एमएसएमई तथा निर्यात में सहायता मिलेगी। उन्होंने रसायनों पर सीमा-शुल्क दरों को अंशशोधित करने की भी घोषणा की ताकि घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन मिल सके।
- उनके अनुसार घरेलु क्षमता को बढ़ाने के लिए सोलर सेल और सोलर पैनलों के लिए चरणबद्ध तरीके से विनिर्माण योजना को अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, सोलर इनवर्टनरों पर शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और सोलर लालटेन पर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया।
- बजट में एमएसएमई को लाभ देने के लिए कुछ बदलावों का भी प्रस्ताव किया गया है जिनमें स्टील स्क्रू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा परिधान, चमड़ा और हस्तशिल्प के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क-मुक्त वस्तुओं के निर्यात पर छूट को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
- किसानों को लाभ देने के लिए, वित्त मंत्री ने कपास पर सीमा-शुल्क को बढ़ाने की घोषण ाा की। उन्होंने इथाइल अल्कोहल पर उद्दीष्ट उपयोग आधारित छूट को वापस लेने की घोषणा की। उनके अनुसार छोटे सामानों पर कृषि बुनियादी ढांचे और विकास शुल्क का भी प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि उपकर को लागू करते समय, हमने अधिकांश मदों पर उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ ना डालने की तरफ भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
- न्यायसंगत अनुप्रयोगों और जटिलताओं को कम करने के संबंध में. वित्त मंत्री ने कहा कि एडीडी और सीवीडी शुल्कों से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलावों का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि सीमाशुल्क जाँच को पूरा करने के लिए, निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जा रही हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की उपलब्धियां

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई):

- 2.76 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज
- 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस
- 40 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधे नकद धनराशि का अंतरण

आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी 1.0):

- 23 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जीडीपी के 10 प्रतिशत से ज्यादा पीएमकेजेवाई, 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबी 1.0, 2.0 और 3.0) इसके अलावा पांच छोटे बजटों जैसी घोषणाएं भी बाद में की गईं।

रचनात्मक सुधार

- एक देश, एक राशन कार्ड
- कृषि और श्रम सुधार
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की पुनः परिभाषा
- खनन क्षेत्र का वाणिज्यीकरण
- कोविड-19 के खिलाफ भारतीय नागरिकों के साथ-साथ कई विदेशियों की सुरक्षा के लिए भारत ने कौवेक्सिन टीका का निर्माण किया है।
- इन वैक्सिन को भारत कई राष्ट्रों को निर्यात कर रहा है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण
- कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई ताजा स्थिति

2021- भारतीय इतिहास में उपलब्धियों का वर्ष

- भारत की आजादी का 75वां वर्ष
- भारत में गोवा के शामिल होने के 60 साल पूरे
- 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे
- स्वतंत्र भारत की आठवीं जनगणना का वर्ष
- ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अब भारत की बारी
- चन्द्रयान-3 मिशन का वर्ष
- हरिद्वार महाकुंभ

आत्मनिर्भर भारत के लिए विजन

- आत्मनिर्भर कोई नया विचार नहीं है, प्राचीन भारत में भी आत्मनिर्भर थी जब भारत पूरी दुनिया के लिए एक कारोबारी केन्द्र था।
- आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतीयों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है।

इसके तहत निम्नलिखित संकल्प मौजूद हैं-

- राष्ट्र पहले
- किसानों की आय दोगुनी करना
- मजबूत अवसंरचना
- स्वस्थ भारत
- सुशासन
- युवाओं के लिए अवसर
- सभी के लिए शिक्षा
- महिला सशक्तिकरण
- समावेशी विकास
- केन्द्रीय बजट 2015-16 में 13 वादे किए गए थे जो देश की आजादी के 75वें वर्ष पर 2022 के अमृत महोत्सव के दौरान आत्मनिर्भरता के विजन के अनुरूप हैं।

"विश्वास वह चिड़िया है जो प्रकाश की अनुभूति करती है और तब गाती है जब भोर में अंधेरा बना ही रहता है।"

-रवीन्द्र नाथ ठाकुर

❍❍❍

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 म्यांमार में सैन्य तख्तापलट : भारत पर प्रभाव

चर्चा का कारण

- हाल ही में, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सेना ने सरकार के खिलाफ सैन्य तख्तापलट कर दिया है और एक वर्ष के आपातकाल के तहत देश की सत्ता को अपने नियंत्रण में कर लिया है। साथ ही देश के मुख्य शहरों की सड़कों पर सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और संचार व्यवस्थाओं पर सीमित रोक लगा दी गई है।

परिचय

- 10 वर्ष पूर्व सेना ने सत्ता का हस्तांतरण जनता की चुनी हुई सरकार को किया था परन्तु म्यांमार में सेना द्वारा वर्ष 2008 में एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया था, और पिछले वर्ष अप्रैल में इस पर संदेहास्पद जनमत संग्रह भी कराया गया था।
- गौरतलब है कि साल 2008 में ही एक संवैधानिक संशोधन किया गया जिसके तहत सेना के पास 25 फीसदी सीटों का आधिकार होगा साथ ही तीन अहम मंत्रालय- गृह, रक्षा और सीमाओं से जुड़े मामलों के मंत्रालय का अधिकार पूरी तरह से सेना के पास होगा।
- माना जाता है कि यह संविधान, सेना ने पश्चिमी देशों के दबाव के कारण निर्मित किया था। और अब तख्तापलट से देश में एक बार फिर डर का माहौल पैदा हो गया है साल 2011 में ही यहां पांच दशकों से चले आ रहे दमनकारी सैन्य शासन का अंत हुआ था परन्तु नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (National league for democracy) की मुखिया आंग सान सू ची और अन्य राजनेताओं की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश में नाउम्मीदी के उस दौर को जिंदा कर दिया है जिससे ये देश एक बार बाहर निकल चुका था।

तख्तापलट का कारण

- आंग सान सू ची और उनकी एक वक्त की प्रतिबंधित रह चुकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी ने 2015 में बीते 25 वर्षों में देखे गए सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के बाद देश का नेतृत्व किया।
- पुन: नवंबर 2020 में हुए चुनाव में आंग सान सू ची की पार्टी एनएलडी को 80 फीसदी वोट मिले। ये वोट आंग सान सूकी की सरकार पर रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के लगने वाले आरोपों के बावजूद मिले।
- इन नतीजों के बाद सेना के समर्थन प्राप्त विपक्षी पार्टी ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया।
- इस संदर्भ में म्यांमार के कार्यकारी राष्ट्रपति जनरल मीएन स्वेने के अनुसार, चुनाव आयोग 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में वोटर लिस्ट की बड़ी गड़बड़ियों को ठीक करने में असफल रहा है। हालाँकि इस आरोप को साबित करने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे।
- इसके अलावा एनएलडी के संवैधानिक सुधार की योजना राजनीति और शासन में सैन्य भूमिका को कम करने के रूप में देखा जा रहा था, इससे सेना को यह आभास हो गया कि सीमित लोकतांत्रिक प्रयोग से भी 'सू की' की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ सैन्य हितों पर भारी खतरा मंडरा रहा है।

सैन्य तख्तापलट का भारत पर प्रभाव

- म्यांमार की सीमा ना केवल भारत से जुड़ी हुई है बल्कि चीन से भी सटी हुई है। ऐसे में म्यांमार में होने वाली गतिविधियों का असर भारत-चीन पर होना स्वाभाविक है। भारत और म्यांमार के बीच 1,640 किलोमीटर की सीमा है। इस सीमा पर ऐसे कई कबाइली समूह हैं जो कि अलगाववादी हैं। ये म्यांमार की सरकार और भारत सरकार के खिलाफ रहते हैं। उत्तर-पूर्व के कई अलगाववादी और उग्रवादी संगठन म्यांमार की जमीन से ही भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित करते हैं।
- हालाँकि भारत ने भी कुछ मौकों पर म्यांमार के अंदर घुसकर इनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। परन्तु भारत म्यांमार में लोकतंत्र का समर्थन करता है और इसलिए भारत सैन्य तख्तापलट का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकता है।
- वर्तमान समय में म्यांमार की सेना के साथ भारत के सुरक्षा संबंध मजबूत हुए हैं, और ऐसे में भारत के लिए उत्तर पूर्वी सीमाओं को विद्रोही समूहों से सुरक्षित करने में म्यांमार सेना की आवश्यकता को देखते हुए यह और मुश्किल हो सकता है।
- जैसे कि अमेरिका द्वारा सेना के इस "तख्तापलट" के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी गयी है, परन्तु हो सकता है कि अमेरिका की तरह भारत की कठोर प्रतिक्रिया से मुख्यत: चीन को लाभ हो।

- इसके अलावा, भारत ने म्यांमार में कई अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं में निवेश किया है।
- साथ ही भारत के लिए अभी भी बांग्लादेश में पलायन करने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे को सुलझाने में मदद करने की उम्मीद है।

म्यांमार के तख्तापलट पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

- वैश्विक स्तर पैर कई देशों ने म्यांमार में तख्तापलट को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है और वहां पुन: पूर्व स्थिति करने की मांग की है।
- जी 7 देशों (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका) ने एक बयान जारी कर कहा है, कि म्यांमार की सेना तुरंत अपातकाल खत्म करे और गणतांत्रिक रूप से चुनी सरकार को उसका स्थान दे। साथ ही वो मानवाधिकार का सम्मान करे और जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है उन्हें रिहा करे।
- इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी अहम बैठक हुई लेकिन इस इमरजेंसी बैठक में 15-सदस्यों वाली काउंसिल को चीन की सहमति हासिल नहीं हो पाई, चीन सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों में से एक है जिसके पास वीटो का अधिकार है।
- चीन का कहना है कि तख्तापलट के बाद यदि म्यांमार पर पाबंदियां लगाई गईं या अंतरराष्ट्रीय दवाब बनाया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं।
- म्यांमार को अंतरराष्ट्रीय स्तर के दवाब से बचाने के लिए चीन पहले भी कोशिश करता रहा है. वो न केवल म्यांमार का मित्र देश है बल्कि आर्थिक तौर पर म्यांमार को बेहद अहम मानता है।
- अल्पसंख्यक रोहिंग्या पर हमलों और उनके पलायन को लेकर रूस और चीन ने पहले भी संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार का बचाव किया था। चीन का कहना है कि उसे उम्मीद है सभी पक्ष आपसी सहमति से मामले को सुलझा लेंगे।

आगे की राह

- म्यांमार की वर्तमान व्यवस्था वहाँ की सेना के लिए काफी फायदेमंद है। यहाँ वाणिज्यिक क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय निवेश है और यह सब कुछ अब सेना के हाथों में है।
- हालाँकि यह हो सकता है कि सेना विपक्षी पार्टी यूएसडीपी को आगे के चुनाव में बेहतर और मजबूत बनाने के लिए ये कर रही हो। परन्तु म्यांमार के लोग एक बार फिर सैन्य सत्ता वाले भविष्य की ओर नहीं बढ़ना चाहते हैं और वे आंग सान सू ची को सैन्य सत्ता के खिलाफ एक चट्टान के तौर पर देखते हैं।
- जानकारों को उम्मीद है कि बातचीत से ये मुद्दा सुलझा लिया जाएगा परन्तु अगर इसके खिलाफ बड़े प्रदर्शन होने लगे तो देश में आन्तरिक संघर्ष स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही माना जा रहा है कि म्यांमार अभी वैश्विक राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा और इस मुद्दे पर अमेरिका और चीन में भी तनातनी बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को अपने पड़ोसी देश म्यांमार से संवाद करने को कोशिश करनी चाहिए ताकि जल्द ही वहाँ स्थायी समाधान खोजा जा सके।
- भारत का मानना है कि म्यांमार की सेना के साथ अच्छे संबंध हमारे पड़ोसी देशों पर चीन के प्रभाव को नियंत्रण में रखेगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजनीतिक सत्ता पलट का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए?

02 बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य एवं भारत की विदेश नीति

चर्चा का कारण

- भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। विदेश नीति निर्धारण का उद्देश्य अपने पड़ोसियों तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करना है और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। हाल के समय में देखा जाए तो कोविड-19 एवं चीन की विस्तारवादी नीति ने वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक संतुलन को बदल कर रख दिया है। पश्चिमी देशों की एकता, जो 1945 अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लगातार बनी हुई है, उसमें एक दरार पड़ी है। उत्तर-अटलांटिक गठबंधन पहले की तुलना में निस्तेज हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका पहले' की नीति ने अमेरिकी गठबंधन प्रणाली की बुनियादी परिकल्पनाओं-धारणाओं को एक चुनौती दी है। इन सब के बीच चीन पश्चिमी देशों में बनी इस अव्यवस्था का फायदा उठा रहा है और वहां अपनी पैठ बना रहा है। इस कारण वैश्विक राजनीति में नए सत्ता-समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत ने भी विश्व के लगभग सभी मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और अधिकांश बहुपक्षीय संस्थानों में उसकी स्थिति मजबूत भी हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति इस बात पर निर्भर करेगी कि वह जी-20 और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कैसी भूमिका निभाता है।

परिचय

- भारत आज विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में से एक है। यह जी-20 का सदस्य है जो सकल विश्व उत्पाद के 85 प्रतिशत और विश्व व्यापार के 80 प्रतिशत भाग का योगदान करता है। यह ब्रिक्स (BRICS) का सदस्य है जो वैश्विक दक्षिण में एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है। यह आसियान के इर्द-गिर्द केन्द्रित संस्थाओं की संरचना के साथ पर्याप्त रूप से एकीकृत है, तथा यह पूर्व एशिया समिट (ईएएस) का भी सदस्य है इसके अतिरिक्त तथा यह पूर्व एशिया के कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त समर्थ भी है।

बदलता वैश्विक भू परिदृश्य

- वर्तमान समय में जन संहारक हथियारों के मसले को नजरअंदाज करना, गंभीर चिंता का विषय है। सशस्त्र नियंत्रण के लिए रूस और अमेरिका के बीच हुए कई समझौते की मियाद पूरी हो चुकी है। अब बाइडेन प्रशासन को यह निर्णय करना है कि रूस के साथ सामरिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (स्टार्ट) की मियाद को आगे बढ़ाया जाए या नहीं।
- बहुपक्षीयवाद (Multilateralism) को गहरा आघात लगा। कोविड-19 के संकट ने दिखाया है कि पूरी दुनिया को बहुपक्षीयवाद से कमतर कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन यह परस्पर देखभाल और साझेदारी के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए न कि ताकत के आधार पर।
- कोविड-19 के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पर कड़ी मार पड़ी है। उसके फिर से पटरी पर आने की गति बहुत धीमी है। इस महामारी ने वैश्वीकरण की खामियों को सामने लाया है। कई देशों में गरीबी उन्मूलन लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के दशकों की अथक मेहनत से जो मुकाम हासिल किया था, वह सब व्यर्थ चला गया।
- तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के गौरव को फिर से पाने की कोशिश कर रहा है। क्षेत्रीय झगड़ों में इसकी भूमिका बढ़ रही है। तुर्की-ईरान-रूस और पाकिस्तान की एक नई धुरी बन रही है। तुर्की और इजरायल के बीच शत्रुता, इसी तरह तुर्की और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी तेज हो रही है। भूमध्यसागर के बीच तनाव बढ़े हैं। यद्यपि तुर्की नाटो का एक सदस्य है, पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं।
- कोविड-19 के दौरान, तेल की वैश्विक खपत में तेजी से गिरावट आई है। इसने मध्य-पूर्व के देशों पर राजस्व उगाही को लेकर जबरदस्त दबाव डाला है। सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को बहुआयामी करने की कोशिश कर रहा है और इसने जी-20 देशों में अपने लिए एक जगह और किरदार की मांग की है। अमेरिका जेसीपीओए (JCPOA) से बाहर आ चुका है। अब देखना यह है कि जो बाइडेन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ कौन सी नीति अपनाते हैं।

चीन और अमेरिका के बीच तनाव

- चीन और अमेरिका दोनों संभवतः एक दूसरे से राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक, प्रौद्योगिकी, सैन्य मामलों और सूचनाओं के क्षेत्र में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, और होड़ कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में जटिल पारस्परिक प्रभावों के कारण लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगी। अमेरिका और रूस के बीच एक नया शीत युद्ध (New cold war) आकार लेने लगा है। इसके अतिरिक्त चीन,रूस और अमेरिका के बीच उभरते टकराव में यूरोप की भूमिका अस्पष्ट है।
- रूस दृढ़तापूर्वक चीन के साथ है। जापान का अमेरिका के साथ संधि है और वह चीन की तरफ से लगातार दबाव झेल रहा है, लेकिन वह उसके साथ अपना कारोबारी संबंध बनाए हुए है। आसियान अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की तरफ देखता है, लेकिन यह चीन के साथ आर्थिक और व्यावसायिक रूप से जुड़ा हुआ है। अतः दो महाशक्तियों के बीच ठनी लड़ाई बिल्कुल सीधी-सरल नहीं होगी। इसमें हानि उठाने वाला कोई कैंप दूसरे कुछ देशों के साथ अपने संबंध बना सकता है और इस तरह वह दोनों पक्षों के साथ बना रह सकता है। ऐसी परिस्थिति में, उन देशों के लिए गुटनिरपेक्षता तो नहीं, लेकिन तटस्थता एक संभावित रणनीति होगी।

भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए?

- कुछ जानकर भारत के पड़ोसी देश चीन और भारत के बीच बने अवरोधों को बहुत सावधानी से देख रहे हैं। चीन ने नेपाल पर अपना राजनीतिक प्रभाव पहले ही स्थापित कर दिया है, जो फिलहाल राजनीतिक विप्लव के दौर से गुजर रहा है। लिहाजा, भारत-नेपाल संबंधों में निवेश करने की जरूरत है।

- पाकिस्तान के अतीत को देखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि वह इस वर्ष भी भारत के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। इसीलिए भारत को बहुत सावधानी से पाकिस्तान में हो रहे घटनाक्रमों पर अपनी सतर्क नजर रखनी चाहिए जिसमें उसके राजनीतिक रूप से अस्थिर होने का खतरा बना हुआ है।
- अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों का निर्वाह करते हुए भी भारत, रूस की उपेक्षा का नहीं कर सकता। रूस से एस-400 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली नहीं खरीदने के लिए भारत पर अमेरिका का दबाव लगातार जारी है। भारत का रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों की नीति का अनुसरण करने के अलावा वह ब्रिक्स, और एससीओ (SCO) के रूप में दोनों एक दूसरे के साथ हैं। भारत को रूस की विदेश नीतियों के रुझानों को सावधानी से देखने की जरूरत है। रूस, भारत का सर्वोच्च रक्षा आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। रक्षा प्रणाली के उत्पादन का संयुक्त उपक्रम रूस के साथ अवश्य शुरू किया जाना चाहिए। रूस और चीन के बीच पहले से ही एक मजबूत रणनीतिक भागीदारी है। इसमें पाकिस्तान, भारत और रूस के बीच दरार डालने की कोशिश करेगा।
- अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां एक रिक्तता पैदा हो जाएगी और अफगान के लोग तालिबान और पाकिस्तान की दया पर आश्रित हो जाएंगे। भारत को इन रुझानों को सतर्कता से देखना चाहिए।
- निश्चित रूप से, भारत के लिए चीन इस वर्ष भी सर्वाधिक सुरक्षा चुनौती देगा। लिहाजा, चीन से मिलने वाले दबावों के मद्देनजर अमेरिका और अन्य देशों के साथ भारत को सुरक्षा सहयोग करना उपयुक्त है। चीन ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर जरा भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई है। राजनयिकों के स्तर से लेकर सेना के स्तर तक होने वाली कई दौरों की बातचीत के बावजूद तनाव कम करने की प्रक्रिया में कोई मदद नहीं मिली है। भारत को चीन के मद्देनजर अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि के उपाय करने होंगे।

- सीमा पर तनाव का हल निकालते हुए, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि चीन इस स्थिति का गलत फायदा न उठा ले तथा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) को लेकर नए तथ्यों को न गढ़ ले। भारत ताइवान के साथ आर्थिक संबंध गहरे करने पर विचार करे, जैसा कि अन्य कई देश इस समय कर रहे हैं।
- यूरोप बदल रहा है। भारत को यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ जहां तक संभव हो कारोबारी समझौते पर काम करना चाहिए।

आगे की राह

- क्वाड के साथ अपनी भागीदारी को लेकर भारत की हिचक कम हुई है। विश्लेषकों ने इन घटनाक्रमों को, भारतीय नीति में अमेरिका के प्रति बढ़ते झुकाव के रूप में विश्लेषित किया है। हिंद महासागर के प्रति अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षी दृष्टि के साथ, भारत ने महाशक्ति की सुनियोजित योजना में अपनी एक जगह तय की है, जो क्षेत्र में बड़ी रणनीति महत्ता के रूप में दिख रही है।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर वीटो प्राप्त सदस्य की दो वर्षीय कार्यावधि की आठवीं बार शुरूआत की है। ऐसे में उसे बहुपक्षीयवाद के अपने के एजेंडे को क्रियान्वित करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव लाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भारत को प्रभावी कूटनीति और विदेश नीति के लिए अपनी अंतर्निहित क्षमताओं और शक्तियों को निर्मित करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में आने वाले वर्षों में भारत को अपनी विदेश नीति में सावधानीपूर्वक बदलाव करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये

03 भारत–श्रीलंका संबंध : चुनौतियाँ एवं अवसर

चर्चा का कारण

- हाल ही में श्रीलंका ने घोषणा की है कि कोलंबो बंदरगाह के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (East Container Terminal- ECT) का पूरी तरह से संचालन सरकारी एजेंसी श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी (Sri Lanka Ports Authority) द्वारा किया जाएगा। श्रीलंकाई सरकार ने देशभर के ट्रेड यूनियनों के कड़े विरोध के बाद यह फैसला किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने कहा है कि कहा कि श्रीलंका कोलंबो पोर्ट के ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के संचालन को लेकर हुए समझौते का पालन करे।

प्रमुख समझौता

- साल 2019 में (राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना–प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे सरकार के दौरान) श्रीलंका ने भारत और जापान (India and Japan) के साथ मिलकर कोलंबो पोर्ट (Colombo Port) पर कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए समझौता किया था। इसमें कहा गया था कि टर्मिनल के संचालन में भारत और जापान की हिस्सेदारी 49 फीसद और शेष 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी श्रीलंका के पोर्ट्स अथॉरिटी के पास होगी। इसको लेकर श्रीलंका में काफी विरोध-प्रदर्शन हो रहा था। कोलंबो बंदरगाह पर पूर्वी कंटेनर टर्मिनल का निर्माण चीन के विवादित 50 करोड़ डॉलर की लागत वाले कंटेनर टर्मिनल के नजदीक किया जा रहा था।

समझौते को रद्द करने का कारण

- **श्रीलंका की अंदरूनी राजनीति:** भारत और जापान के साथ इस समझौते का कोलंबो पोर्ट ट्रेड यूनियंस विरोध कर रहे थे। यूनियंस की मांग थी कि ECT पर पूरी तरह से श्रीलंका पोर्ट का अधिकार हो यानी 100 फीसदी हिस्सा उसके जिम्मे हो। 23 ट्रेड यूनियंस ने पोर्ट डील का विरोध किया था। यूनियंस का आरोप था कि भारत की अडाणी समूह के साथ ECT समझौता सही नहीं है। श्रीलंका में हर सरकार ट्रेड यूनियन को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर उनका दखल बहुत है। राजनीति में उनकी नाराजगी किसी भी पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। यही वजह है कि पिछली सरकार ने एमओयू साइन तो किया, लेकिन उनके कार्यकाल में भी ये काम शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में जाहिर है कि अगर स्थानीय ट्रेड यूनियन की तरफ से भारत के इस परियोजना में शामिल होने का विरोध हो रहा है, तो सत्ताधारी पार्टी उनकी नाराजगी का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी।
- **चीन का प्रभाव:** जानकारों का मानना है कि चीन का श्रीलंका पर काफी प्रभाव है। चीन, श्रीलंका को उसके महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड का अहम किरदार मानता रहा है। चीन ने पिछले दशक में श्रीलंका की कई अहम परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का लोन दिया था। दरअसल, चीन दक्षिण एशिया में अपना एकछत्र वर्चस्व कायम करना चाहता है, ऐसे में उसकी नजर श्रीलंका पर है। उसने श्रीलंका में भारी मात्रा में निवेश भी किया है। कर्ज नहीं चुकाने पर चीन ने 2017 में श्रीलंका से उसका हंबनटोटा बंदरगाह भी अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि श्रीलंका को चीन द्वारा दिए गए लोन से ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है उसे इसको वापस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, मारिशस, म्यांमार या बांग्लादेश, चीन की बंदरगाहों और समुद्रतटीय इलाकों में दिलचस्पी असाधारण रूप से बढ़ी है। मालदीव और श्रीलंका में चीन के असफल निवेशों के बाद से यह भी साफ हो चला है कि उसकी ऋण जाल कूटनीति (debt-trap diplomacy) उसके लिए काफी कारगर हो रही है।
- इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रीलंका का यह निर्णय सीधे सीधे चीन से जुड़ा हुआ है। चीन और भारत के बीच पिछले कई महीनों से सीमा पर विवाद और सेनाओं के आमने सामने डटे होने से यह बात ज्यादा स्वाभाविक भी लगती है।
- **सिंहला समुदाय का मुद्दा:** तमिल समुदाय को श्रीलंका में अल्पसंख्यक माना जाता है, भारत की तरफ से किसी भी तरह की मदद को वहाँ के स्थानीय लोग भारत के बढ़ते दबदबे के तौर पर देखते हैं। इसलिए वहाँ के पोर्ट यूनियन वाले नहीं चाहते कि भारत की मदद से वहाँ इस तरह का कोई काम हो।

ईस्ट कंटेनर टर्मिनल क्यों महत्वपूर्ण है ?

- सामरिक नजरिए से ये कंटेनर टर्मिनल बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। उस इलाके का लगभग 70 फीसदी कारोबार इसी के जरिए होता है। ये ट्रांसशिपमेंट कोलंबो के नजदीक है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत इसका सबसे ज्यादा उपयोग भी करता है।

श्रीलंका द्वारा भारत के लिए प्रतिपूरक प्रस्ताव

- श्रीलंका सरकार ने अब ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की जगह वेस्ट कंटेनर टर्मिनल भारत के सहयोग से बनाने का प्रस्ताव दिया है। नए प्रस्ताव के तहत श्रीलंका इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर भारत और जापान के साथ ही मिल कर बनाना चाहता है। जानकारों का मानना है कि व्यावसायिक रूप से पश्चिमी टर्मिनल भारत के लिये बेहतर है क्योंकि यह ईस्ट कंटेनर टर्मिनल में 49% के विरुद्ध पश्चिम टर्मिनल के डेवलपर्स को 85% हिस्सेदारी प्रदान करता है। भू-राजनीतिक रूप से भी वेस्ट टर्मिनल, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के समान है। ईस्ट टर्मिनल की तुलना में वेस्ट टर्मिनल आकार या गहराई में छोटा नहीं है। हालांकि भारत इस प्रस्ताव से लेकर बहुत उत्साहित नहीं है।

भारत- श्रीलंका संबंधों पर प्रभाव

- हिंद महासागर क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में भारत हमेशा श्रीलंका की एकता, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति कटिबद्ध रहा है। किन्तु श्रीलंका द्वारा किए गए हालिया निर्णय से भारत और जापान जैसे दो महत्वपूर्ण पड़ोसियों से श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंध बिगड़ने की नौबत आ सकती है।
- भारत ने कुछ दिन पहले ही नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत श्रीलंका को कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज फ्री में दी थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने भारत की उदारता के लिए पीएम मोदी और भारत का आभार भी जताया था। किन्तु ईसीटी समझौते को रद्द करने के साथ श्रीलंकाई सरकार ने दर्शा दिया है कि वह अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के बारे में बहुत चिन्तित नहीं है।
- कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत भू-राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर श्रीलंका को अलग-थलग कर सकता है और महामारी के बीच आर्थिक अलगाव श्रीलंका के लिये मुश्किलें पैदा कर सकता है। किन्तु इसके विपरीत जानकारों का मानना है कि इससे भारत को ज्यादा नुकसान हो सकता है।

आगे की राह

- भारत के लिए रणनीतिक रूप से श्रीलंका अहम है। समुद्र के रास्ते भारत में ज्यादातर सामान की आवाजाही श्रीलंका के रास्ते ही होती है। इसके अतिरिक्त वैश्विक परिप्रेक्ष्य में श्रीलंका सामरिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से भारत का एक अहम पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंध सदियों प्राचीन हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरूमध्य एक विभाजनकारी आभासी लकीर है। श्रीलंका के साथ संबंधों में मजबूती भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बनाए रखने का अभूतपूर्व प्रयास किया है ताकि वर्तमान के वैश्विक युग में भारत के साथ-साथ पड़ोसी देशों का भी बेहतर माहौल में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास अबाधित रूप से होता रहे। भारत सरकार द्वारा श्रीलंका के साथ संबंधों को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। संबंधों को बेहतर बनाने हेतु आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक कूटनीति के साथ साथ सांस्कृतिक कूटनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक कूटनीति पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।
- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।
- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

प्र. श्रीलंका द्वारा ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट से भारत को अलग करने से आपसी संबंधों में पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिये।

04 अमेरिका की वर्तमान विदेश नीति एवं उसका वैश्विक प्रभाव

चर्चा का कारण

- 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन (Joe Biden) ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रंपति के रूप में शपथ ले ली है। जो बाइडेन के साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। अपने उद्घाटन भाषण में, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया को एकता और आशा का संदेश दिया। विश्लेषकों का मानना है कि जो बाइडेन आदर्शवादी होने के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गहराई से सोचने वाले सकारात्मक और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो बाइडेन को बधाई देते हुए कहा कि भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने इच्छा रखता है ।

परिचय

- अमेरिका की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बहाल करने और अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कोशिश में, उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती, जो बाइडन को कोरोना वायरस से निपटने के लिए अब कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि अमेरिका अभी तक कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने में असफल रहा है। उनके सामने दूसरी बड़ी चुनौती अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की और उसे पटरी पर लाने की है। अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाने के कारण अमेरिका का मध्यमवर्गीय समाज प्रभावित हुआ है। इस कारण समाज में बंटवारे और आय की असमानता को दूर करना उनके लिए तीसरी बड़ी चुनौती है। अमेरिका की चौथी बड़ी समस्या रंगभेद का मुद्दा है, जिसने अमेरिकी समाज को दो वर्गों में बांट दिया है। इससे वहां सामाजिक सौहार्द बिगड़ चुका है।
- हाल में अमेरिकी संसद में हुई हिंसा के कारण दुनिया के अन्य देशों में अमेरिका की छवि धूमिल हुई है। अमेरिका की छवि को सुधारने के लिए उन्हें पुनः पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी लोकतंत्र का सही स्वरूप पेश करना होगा।

अमेरिका की चीन नीति

- विश्लेषकों के मुताबिक नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को बहुत जल्द ही एहसास हो चुका है कि वैश्विक वातावरण आज उस वक्त से बहुत अलग है जब वह उप-राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। ओबामा-युग की नीतियों की पूर्व वापसी, वर्तमान समय में अपर्याप्त साबित हो सकती है। दुनिया आगे बढ़ गई है और कई नीतियों को नए तरीके से बदलाव करने की आवश्यकता होगी। जो बाइडन अमेरिका की विदेश नीति को एक नई दिशा देते हुए एक ऐसी रणनीति बना सकते हैं, जिसमें एशिया और यूरोप के सहयोगी देशों के साथ मिलकर चीन से निपटा जा सके। संभव है वह चीन को लेकर शायद ट्रंप की तरह आक्रामक न हों, पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि उनका रवैया चीन को लेकर नरम होगा। राष्ट्रपति बाइडन विदेश नीति में सैन्यीकरण (militarisation) के पक्ष में नहीं हैं, मगर डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में कई विवादास्पद विदेश नीति के मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने के पक्ष में जरूर हैं।
- चीन से कैसे निपटा जाए? इस प्रश्न पर जो बाइडन बहुत खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, किन्तु जानकारों का मानना है कि चीन, वर्तमान में अमेरिकी चुनौतियों का सामना करने वाला एकमात्र देश नहीं है, फिर भी चीन से अमेरिका को आर्थिक और तकनीकी खतरे दिखाई देते हैं। एशिया के कुछ देश पड़ोसी चीन के खिलाफ मुखर हैं। पूर्वी एशिया विशेषकर ताइवान में चीन के बढ़ते दखल की वजह से एशिया में एक समावेशी सुरक्षा वास्तुकला तैयार करने की जरूरत महसूस होने लगी है। चूंकि पूर्वी एशिया में अमेरिका के व्यापारिक एवं सामरिक हित जुड़े हुए हैं, ऐसे में अमेरिका टकराव की ओर जाने का प्रयास नहीं करेगा बल्कि वह सुलह का प्रयास करेगा। जानकारों के अनुसार चीन से मुकाबला करने के लिए इलाके के वैसे देशों से गठजोड़ करने की जरूरत है जो उदार अर्थव्यवस्था वाले हैं और अमेरिका के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया में चीन के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका, भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा सकता है।
- शीत युद्ध के बाद रूस भले अमरीका की तुलना में कमजोर हुआ, लेकिन अगर वो आज भी किसी देश के साथ खड़ा होता है तो अमरीका के कान खड़े हो जाते हैं। वर्तमान में चीन और रूस की नई रणनीतिक जुगलबंदी दिखाई दे रही है। पश्चिम के कई पर्यवेक्षकों ने इस जुगलबंदी को अमरीका के खिलाफ रूस और चीन की साझी तैयारी के तौर पर पेश किया है। देखा जाये तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और उसके सहयोगियों को रोकने के लिए साथ मिलकर कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। ऐसे में अमेरिका को अपने पूर्व में किए गए निर्णय एवं पहल को नई नीति निर्देशों के साथ आना होगा।

अमेरिका के यूरोप एवं पश्चिम एशिया के साथ संबंध

- जब यूरोप के साथ अमेरिका के संबंधों को सुधारने की बात आती है तो राष्ट्रपति बाइडेन के समक्ष कई कठिन कार्य दिखाई देते हैं। कुछ वर्षों पूर्व यूरोप और अमेरिका समान नीति पर कार्य करते थे किन्तु डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में अमेरिका की यूरोप से तल्खी बढ़ी थी। यूरोप का प्रमुख देश जर्मनी संभवतः यूरोप के केंद्र के रूप में उभर रहा है और वो चीन और रूस जैसे देशों के साथ यूरोप के संबंधों को निर्धारित करने में लगा हुआ है। जानकारों के अनुसार क्रेमलिन के आलोचक एलेक्सी नवेलनी (Alexei Navalny) को जहर देने के मामले में रूस घिरा हुआ था। राजनीतिक स्तर पर तो उसकी आलोचना हुई ही थी लेकिन जर्मनी ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि उसने मामले की जांच में सहयोग नहीं किया, तो वह जर्मनी-रूस गैस पाइपलाइन परियोजना 'नॉर्ड

स्ट्रीम 2' (Nord Stream 2) रोकने पर विवश हो जाएगा। किन्तु बदलते समीकरण के साथ रूस के मानवाधिकार रिकॉर्ड खराब होने के बावजूद जर्मनी, अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद, रूस के नेतृत्व वाली गैस पाइपलाइन परियोजना नॉर्ड स्ट्रीम 2 के साथ आगे बढ़ने में संकोच नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद, यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापक समझौता, यूरोप की नई स्वतंत्र सोच का संकेत है।

- अमेरिका ने बीते कई दशकों से पश्चिम एशिया में अपना दबदबा कायम रखा है। फिर भी यहाँ अमेरिकी प्रशासन के लिए समस्याएँ बहुत ज्यादा हैं। सीरिया और यमन गृहयुद्ध में उलझे हुए हैं। यहाँ राजनीतिक समाधान खोजना अमेरिका के लिए अब तक टेढ़ी खीर साबित हुई है। हालांकि सऊदी अरब के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं किन्तु इजरायल के साथ सऊदी अरब के संबंध खराब हैं। फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प ने "अब्राहम समझौते" के जरिये इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता कराया है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे। हो सकता है बाइडेन सरकार इतिहास में मध्य पूर्व को लेकर ओबामा प्रशासन में क्या गलतियां हुई थीं उन गलतियों से सीखकर चीजों को अलग दिशा में ले जाएं।
- अमेरिका की विदेश नीति में फिलहाल सबसे ऊपर ईरान की जगह होगी। अब देखना है कि बाइडेन सरकार ईरान समस्या से निपटने के कौन से तरीके अपनाएगा। वैश्विक शक्तियों ने 2015 में जो परमाणु समझौता किया था, वो आज मझधार में लटका पड़ा है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को उस समझौते से अलग कर दिया था और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके अलावा, यमन का विनाशकारी युद्ध भी है, जिसका ओबामा ने शुरुआत में समर्थन किया था ताकि ईरान के साथ समझौते से नाराज सऊदी अरब को शांत किया जा सके। किन्तु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी है।

अमेरिका का भारत के प्रति दृष्टिकोण

- कई वर्षों से भारत और अमेरिका के बीच बड़े अच्छे द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंध रहे हैं। अब भारत की नजरें खास तौर पर जो बाइडेन प्रशासन की विदेश नीति और इस विदेश नीति के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव पर रहेंगी। भारत उम्मीद करता है कि बाइडेन प्रशासन पूर्ववर्ती रिपब्लिकन प्रशासन की तुलना में अधिक अनुकूल साबित होगा। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते की सफलता जो बाइडेन के उपराष्ट्रपति कार्यकाल में सम्पन्न हुई थी। बाइडेन प्रशासन भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को और अधिक बढ़ाने की संभावना है, कम से कम ऐसे समय तक जब तक अमेरिका-चीन संबंधों में सुधार नहीं हो जाता है।
- शीत युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका के खेमे में शामिल होने से इनकार कर दिया था। भारत तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल था। ऐसे में अमेरिका की करीबी पाकिस्तान से ज्यादा रही है क्योंकि वो शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका के ही खेमे में था। भारत के लिए पूरी तरह से अमेरिका के खेमे में जाना इतना आसान भी नहीं है। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेइ लवरोफ ने क्वॉड गुट पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत को चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों की लगातार, आक्रामक और छलपूर्ण नीति में एक मोहरा बनाया जा रहा है।

अमेरिका की अफगान नीति

- बाइडन प्रशासन पूर्व के ट्रंप प्रशासन द्वारा अफगानिस्तान में सभी पक्षों के साथ किए गए समझौते का पूरी तरह से समर्थन करता है। ट्रंप प्रशासन ने फरवरी 2020 में दोहा में तालिबान के साथ समझौता किया था। समझौते के अनुसार अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही सभी पक्षों ने अफगानिस्तान में शांति के लिए अपनी गारंटी दी थी। तालिबान ने अलकायदा सहित अन्य संगठनों के अफगान की धरती पर हिंसा न करने और अमेरिकी सेना पर हमला न किए जाने का गारंटी दी हुई है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि हम इसी नीति पर आगे बढ़ेंगे।

आगे की राह

- आज अमेरिका और भारत के बीच सामरिक मसलों पर काफी समान विचार देखने को मिल रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भारत और अमेरिका को अपने संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। भारत की सामरिक चुनौती मुख्य रूप से हिंद महासागर की पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी सीमा की ओर से आती है। ऐसे में जरूरी है कि भारत और अमेरिका अपने संबंधों को मजबूत बनायें ताकि दोनों देशों के हित सध सकें।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

प्र. यूरोप एवं पश्चिम एशिया में बदलते समीकरण के बावजूद,भारत और अमेरिका इन क्षेत्रों में अपने सम्बन्धों को कैसे बेहतर बना सकते हैं? चर्चा कीजिये।

05 परमाणु हथियार निषेध संधि : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

- संयुक्त राष्ट्र की पहल पर नाभिकीय अस्त्र निषेध संधि (Tveaty on the Prohibition of nuclear weapons-TPNW) 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है, परन्तु इस कानून पर अभी से संकट के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने ही इसका कड़ा विरोध किया है जिसमें भारत सहित 9 बड़े देश शामिल हैं।
- सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जिस जापान ने परमाणु हमले की मार झेली है वह भी इस कानून का विरोध करने वालो के साथ खड़ा है, ऐसे में सवाल यह है कि जिन देशों को परमाणु हथियार नहीं बनाने का प्रण सबसे पहले लेना चाहिए था अगर वही इसका विरोध करने लगेंगे तो दूसरे देशों को किस आधार पर परमाणु हथियार बनाने से रोका जायेगा?

परिचय

- वैसे तो विश्व को विनाशकारी परमाणु हथियारों से बचाने की इस पहल को ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है क्योंकि तमाम देशों में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने की होड़ ने मानव जाति के बड़ा खतरा पैदा कर दिया है और अब तो दुनिया के कुछ देशों ने हाइड्रोजन बम और उससे खतरनाक परमाणु हथियार बना लिए है। इसी खतरे को बढ़ने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने इस संधि को जुलाई 2017 में मंजूरी दी थी, जिसे 120 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था।
- संधि में वर्तमान में 52 सदस्य राज्यों के साथ 86 हस्ताक्षर कर्ता हैं। यह अब अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा है।
- संधि में व्यापक रूप से विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारण, रख-रखाव, स्थानांतरण, और परमाणु हथियारों से संबंधित उपयोग के खतरे आदि को शामिल किया गया है। पहले के प्रस्तावित समझौते जैसे गैर परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (The comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty-CTBT) में इन सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया गया था।
- यह संधि पिछले संधियों के विपरीत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नैतिक आयाम तक ही सीमित नहीं हैबल्कि इसका लक्ष्य इस पृथ्वी पर मानव जीवन को संरक्षित करना है। संधि के प्रावधान सभ्यता के अस्तित्व को समाप्त करने वाले प्रलय की तरह संभावित खतरे वाली घटना पर आधारित हैं।
- हालाँकि परमाणु हथियारों को पहले इस्तेमाल नहीं करने और दुसरे देशों को ऐसे हथियार बनाने से रोकने को लेकर पहले भी कई संधियाँ हुई है कई तरह की व्यवस्थायें बनीं है परन्तु परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र ही इन्हें तोड़ते रहे हैं और परिणाम स्वरूप आज सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास है क्योंकि ये परमाणु हथियारों को लेकर की संधियों पर अमल नहीं करते ऐसे में हर देश भी चाहता है कि वह विकसित देशों की तरह परमाणु ताकत बने लेकिन पहले से मौजूद परमाणु ताकतें जब उसे रोकती है तो वह गुपचुप परमाणु कार्यक्रम चलाता है जिसके उदहारण उत्तर कोरिया और ईरान है।

संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि के प्रमुख प्रावधान

- परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध (The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons-TPNW) संधि में हथियारों से संबन्धित किसी भी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंधों के व्यापक प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है-
  - यह संधि सदस्य देशों को उनकी राष्ट्रीय सीमा के भीतर परमाणु हथियारों को विकसित करने और उनकी तैनाती को प्रतिबंधित करती है और निषिद्ध गतिविधियों के संचालन में किसी भी राज्य को सहायता करने पर रोक भी लगाती है।
  - यह संधि सदस्य राज्यों को उनके क्षेत्राधिकार में या नियंत्रण क्षेत्र में TPNW के तहत निषिद्ध किसी भी गतिविधि को रोकने और दबाने के लिए बाध्य करती है।
  - इस संधि के तहत सदस्य राज्य परमाणु हथियारों के उपयोग या परीक्षण से प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, साथ ही इन हथियारों के उपयोग या परीक्षण से प्रभावित उनके

अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में पर्यावरणीय उपचार के आवश्यक और उचित उपाय करने के लिए संबंधित गतिविधियों भी संचालित करनी होंगी।

परमाणु सम्पन्न देशों द्वारा संधि विरोध का कारण

- जिन देशों ने छनबसमंत ˘मंचवद ंठद ज्तमंजल का समर्थन नहीं किया था उनमें भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। इन 9 देशों के साथ 30 देशों के संगठन नाटो ने भी इसका समर्थन नहीं किया था।
- इस संदर्भ में भारत का कहना हैं कि वह "निरस्त्रीकरण पर जिनेवा में हुए सम्मेलन" को एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में मान्यता देता है, लेकिन वैश्विक रूप से निरस्त्रीकरण मुद्दे को संबोधित करने में वर्तमान संधि सक्षमता पर आशंका भी व्यक्त करता है। साथ ही चूँकि भारत ने परमाणु हथियार निषेध पर संधि पर वार्ता में भाग नहीं लिया, इसलिए भारत इस संधि का हिस्सा नहीं बनेगा।
- वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का कहना हैं कि यह परमाणु निरोध के महत्व को नजरंदाज करती है, यह संधि उत्तर कोरिया जैसे देशों के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न गंभीर खतरे की पृष्ठभूमि में, वैश्विक शांति और स्थिरता को खतरा उत्पन्न कर सकती है।

जापान द्वारा संधि विरोध का कारण

- जापान के अनुसार इस संधि को लेकर उसका दृष्टिकोण अलग है। जापान के अनुसार यह संधि यथार्थवादी नहीं है एवं यह संधि गैर परमाणु राज्य एवं परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के मध्य एक विभाजन की स्थिति पैदा करता है। इसीलिए जापान ने बीच का रास्ता अपनाते हुए दोनों पक्षों के संकरे अंतर को कम करने हेतु इस विकल्प को चुना है।
- इसके साथ ही जापान ने अपने समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को भी इंगित किया है, जहाँ पर उसे चीन और उत्तर कोरिया से खतरा है।
- पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण चीन सागर में चीन का लगातार आक्रामक रुख एवं कोरिया प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया के द्वारा लगातार हथियारों के परीक्षण जापान की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा देते हैं। तात्कालिक सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर पिछले कुछ वर्षों से जापान के द्वारा सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए ना केवल सैन्य बजट बढ़ाया गया है बल्कि अत्याधुनिक हथियारों से जापान सेना को सुसज्जित भी करना प्रारंभ किया है।

- उपरोक्त चुनौतियों को देखते हुए जापान ने परमाणु शक्ति के संदर्भ में न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के अपने विकल्पों को खुला रखा है।

निष्कर्ष

- अब भी एक बड़ा सवाल यह है जब परमाणु अप्रसार संधि 1970 से प्रभावी है तो नई संधि की जरूरत क्यों महसूस हुई? पांच दशक के दौरान एनपीटी का कितना पालन हुआ? क्योंकि अगर एनपीटी पर दस्तखत करने वाले देश अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियारों की होड़ को लेकर संयम बरता होता तो शायद आज अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य कुछ और होता।
- इसलिए जब तक दुनिया के परमाणु शक्ति सम्पन्न देश अपने हथियार नष्ट नहीं करेंगे और भविष्य में इनका निर्माण बंद नहीं करेंगे तब तक दूसरे देशों को इस दिशा में बढ़ने से रोक पाना संभंव नहीं होगा। इससे कहीं ना कहीं यह जाहिर होता है कि परमाणु शक्ति सम्पन्न देश अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं और अगर ऐसे ही हर देश अपनी सुरक्षा और शक्ति संतुलन के नाम पर परमाणु हथियारों की दौड़ में बना रहेगा तो धरती को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने का सपना कैसे साकार होगा?
- निष्कर्षत: हम परमाणु हथियारों के उपयोग और परीक्षण के विनाशकारी परिणामों को भूल नहीं सकते, जिस तरह परमाणु बम के बचे हुए लोग हमें याद दिलाते हैं कि फिर से परमाणु हथियार का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि शांति और बहुपक्षीय सहयोग की उन्नति में योगदान किया जाए, जो इस वक्त की मानवीय आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. परमाणु हथियारों का प्रसार और उनका उपयोग वर्तमान वैश्विक सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौती है परन्तु फिर भी विश्व के अधिकांश देशों द्वारा परमाणु हथियार निषेध संधि का विरोध कितना उचित है? समीक्षा करें।

06 पुरानी होती बांध अवसंरचना : एक वैश्विक चुनौती

चर्चा का कारण

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 में एक हजार से अधिक बड़े बांध लगभग 50 वर्ष पुराने हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 2050 तक भारत के करीब 4,250 बड़े बांध 50 वर्ष की उम्र को पार कर जाएंगे, जबकि 64 बड़े बांध 150 वर्ष या उससे ज्यादा पुराने होंगे। विश्लेषकों का मानना है कि दुनिया भर में इस तरह के पुराने ढांचे भविष्य में खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के कनाडा के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान द्वारा संकलित एजिंग वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर: एन इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क्श नामक रिपोर्ट (Ageing water infrastructure: An emerging global risk) के अनुसार दुनियाभर में 58,700 बड़े बांधों में से अधिकांश का निर्माण 1930 और 1970 के बीच किया गया था, जिनकी उम्र 50 से 100 साल के बीच रखी गयी थी।
- कंक्रीट से बना बांध 50 साल के बाद पुराना हो जाता है। इस स्थिति में बांध विफल होने लगते हैं, उनकी मरम्मत में ज्यादा पैसा खर्च होने लगता है, बांधों में गाद ज्यादा जमा होने लगता है और बांध का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगता है। इसलिए दुनिया के हजारों बांध इस समय खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक दुनिया की ज्यादातर आबादी 20वीं सदी में बने इन हजारों बांधों के नीचे की ओर बसी होगी और इसके चलते पुराने बांधों से उन्हें गंभीर खतरा होगा।
- रिपोर्ट में यह बात भारत, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान, जांबिया और जिम्बाब्वे में बने बांधों का अध्ययन करने के बाद कही गई है। 32 हजार से ज्यादा बड़े बांध एशियाई देशों में हैं। रिपोर्ट के अनुसार कुल बांधों के 55 प्रतिशत यानी 32,716 बड़े बांध चार एशियाई देशों-चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया में हैं। इनमें से ज्यादातर जल्द ही 50 साल से ज्यादा पुराने हो जाएंगे।

- जलवायु परिवर्तन इन बांधों को और कमजोर कर रहा है, जिस तरह से बाढ़ और अन्य चरम मौसमी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, उससे यह बांध जल्द कमजोर हो रहे हैं। इनके बढ़ती उम्र न केवल लाखों लोगों के लिए खतरा पैदा कर रही है, साथ ही इनकी मरम्मत और रखरखाव के खर्च को भी और बढ़ा रही है। इससे ने केवल लोगों का जीवन बल्कि साथ ही पर्यावरण को भी खतरा है।

भारत के संदर्भ में

- भारत में 2025 तक 1,115 बड़े बांध ऐसे होंगे जो 50 साल के होंगे। 2050 में 4,250 बड़े बांध ऐसे होंगे जो 50 साल से ज्यादा उम्र के होंगे। 2050 तक 64 बड़े बांध ऐसे होंगे जो 150 साल की मियाद पूरी कर चुके होंगे। केरल में एक ऐसा ही बांध है जिसका नाम है मुल्लापेरियार बांध। यह बांध 100 साल पहले बना है। अगर यह बांध विफल होता है तो 35 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। यह बांध ऐसा है जिसे लेकर तमिलनाडु और केरल में बराबर विवाद बना रहता है।

वैश्विक संदर्भ में

- पर्यावरण और जान माल के लिए बड़ा खतरा अमेरिका और यूरोप के बांधों को लेकर भी जताया गया है। पुराने बांधों की मरम्मत करने या अपग्रेड करने में कुछ आर्थिक और व्यावहारिक दिक्कतें हैं जिस वजह से इनका काम रुका पड़ा है। अमेरिका में औसतन 90,580 बांध ऐसे हैं जिनकी उम्र 56 साल है। अमेरिका के 85 फीसद बांध 2020 में अपनी क्षमता से ज्यादा काम करते पाए गए। इनकी डिजाइन उम्र पार हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। अमेरिका में बांधों की मरम्मत पर अनुमानित लागत 46 बिलिनय डॉलर है। अमेरिका के 21 राज्यों में पिछले 30 साल में 1275 बांधों को बंद कर दिया गया है जबकि 80 बांध 2017 में बंद कर दिए गए थे।
- इसी तरह चीन में करीब 30000 बांध उम्रदराज हो चुके हैं।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में जितने बांध हैं उनमें अनुमानतः 7 हजार से 8300 क्यूबिक किलोमीटर पानी जमा है। यह पानी इतना है जो कि कनाडा जैसे देश की 80 फीसद आबादी को कवर कर सकता है। यह रिपोर्ट जारी करने के पीछे मकसद यह है कि बांधों की सुरक्षा पर सरकारों और एजेंसियों का ध्यान खींचा जाए। पुराने पड़ते बांधों को अपग्रेड करने या उन्हें बंद करने के बारे में फैसला लिया जा सके ताकि लोगों की जिंदगी खतरे में न पड़े।

क्या होते हैं बड़े बांध?

- इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स (International Commission on Large Dams) के अनुसार जिन बांधों की ऊंचाई 15 मीटर या उससे ऊपर है साथ ही जो 30 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी को संजो सकते हैं उन्हें बड़े बांधों की श्रेणी में रखा जाता है।
- यदि दुनिया के समस्त बड़े बांधों को देखें तो यह सभी मिलकर 7,000 से 8,300 क्यूबिक किलोमीटर पानी को संजो सकते हैं, जोकि सालभर में नदियों द्वारा प्रवाहित होने वाले कुल जल का करीब 16 फीसदी है। गौरतलब है कि दुनिया की 40 फीसदी उपज इन्हीं बांधों पर निर्भर है।

भारत में बांधो का रखरखाव

- भारत 5,334 बड़े बांधों के साथ चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। इसके अलावा, वर्तमान में लगभग 411 बांध निर्माणाधीन हैं। ये बांध देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारतीय बांध और जलाशय सालाना लगभग 300 अरब क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण करके हमारे देश की आर्थिक और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में बांधो का निर्माण और उनकी मरम्मत की निगरानी केंद्रीय जल आयोग करता है।
- भारत के बांध पोर्टफोलियो के आकार और इन मौजूदा परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार देश भर में बांध सुरक्षा पेशेवरों के समूह की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।
- जल विद्युत सुरक्षा में सुधार के लिए संरचनात्मक उपायों के अलावा, चुनिंदा बांधों के लिए हाइड्रो-मैकेनिकल उपायों, रिसाव में कमी, संरचनात्मक स्थिरता आदि, गैर-संरचनात्मक उपायों जैसे बांध विराम विश्लेषण, आपातकालीन कार्य योजना, संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) मैनुअल की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा बांधों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी प्रणाली विकसित की गयी और इस समय 18 राज्य इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त एक भूकंपीय खतरा विश्लेषण सूचना प्रणाली (एसएचएआईएसवाईएस) भी विकसित की गयी है।
- मौजूदा डीआरआईपी से मिली गति को आगे बढ़ाने के लिए और इसे लंबवत और क्षैतिज रूप से विस्तारित करते हुए शुरू की गयी नयी योजना डीआरआईपी चरण 2 के दायरे में देश के 19 राज्यों में बड़े बांध शामिल किए गए हैं।

आगे की राह

- भारत सरकार का प्रयास होना चाहिए कि वह बांध की नाकामी के जोखिम को देखते हुए, नदी की पारिस्थितिकी और इन चुनिंदा बांधों की निचली जलधारा के पास स्थित संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करे। साथ ही सरकार को संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों जैसे पुनर्वास, संचालन और रखरखाव, आपातकालीन कार्य योजना, अर्ली वार्निंग सिस्टम और कई अन्य उपायों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- राज्य के सिंचाई विभाग और केंद्रीय जल आयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि बांधों का निरीक्षण संबंधित राज्य की सरकार करे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

प्र. देश में कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के लिए बांधों के महत्व पर प्रकाश डालिए, इसके अतिरिक्त बांधों की सुरक्षा के लिए उपाय भी सुझाएँ।

07 बिग-टेक कंपनियाँ : वैश्विक अविश्वास एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

- एकाधिकारवादी शक्ति के दुरुपयोग के मुद्दे पर फेसबुक और गूगल जैसी बिग टेक फर्म यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में संदेह के घेरे में आ गए हैं।
- नीति-निर्माताओं के पास इन इंटरनेट फर्मों को विनियमित करने की आवश्यकता से अधिक, उनके एकाधिकार शक्ति के दुरुपयोग को रोकना एक कठिन कार्य है।
- ज्ञातव्य है कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ जिन्हें GAFA (गूगल, अमेजॅन, फेसबुक, एप्पल) के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख कंपनियाँ हैं।

पृष्ठभूमि

- 21वीं सदी के प्रारम्भ में कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर को पावर देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकाधिकार बनाया था।
- दो दशक बाद अमेजॅन, ऐप्पल, फेसबुक और Google द्वारा भी एकाधिकार लाया गया और अब उसका दुरूपयोग हो रहा है। अमेजॅन, ऐप्पल और Google पर आरोप लगाया गया है कि वे प्रतिस्पर्धियों को पीछे करकर अपने स्वयं के उत्पादों के खोज परिणामों के शीर्ष पर ले जाते हैं, भले ही वो आवश्यकतानुसार योग्य हो या नहीं। वहीं फेसबुक भी अकसर विघटन, गलत सूचना और अभद्र भाषा के प्रसार को रोकने में विफल रहा है।
- इस संदर्भ में यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट जैसे विचारों को भी पेश किया है, जो यह दर्शाते हैं कि बड़े यूजर बेस वाली कितनी कंपनियां, प्रतिस्पर्धी और डिजिटल सर्विसेज एक्ट से यूजर्स के लिए अपने खुद के उत्पादों को बढ़ावा दे सकती हैं, जो कंपनियों पर दबाव बनाएंगे एवं अपने प्लेटफार्मों को मॉडरेट करने के लिए एक बेहतर काम करेंगे।

अमेरिका में एंटी-ट्रस्ट जांच

- अमेरिका ने इन कंपनियों के विरुद्ध एंटी ट्रस्ट सर्वेक्षण शुरू की इस। सर्वेक्षण द्वारा एक व्यापार समूह के सदस्यों की आलोचना की गई थी, जो उपभोक्ताओं को वाहक बनाने के लिए इसे कठिन बना रहे थे। पिछले साल भी एंटीट्रस्ट जाँच के दौरान Google पर आरोप लगाया कि उसने एक्सक्लूसिव बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट कर अपने प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाया है।
- वहीं जनवरी माह में यूरोपीय संघ के एंटीट्रस्ट नियामकों ने विज्ञापनदाताओं से Google एडवरटाइजिंग टेक्नोलॉजी प्रेक्टिस के बारे में जानकारी मांगी थी क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग, एंड्रॉयड स्मार्टफोन और ऑनलाइन विज्ञापन में प्रतिद्वंद्वियों को रोकने के लिए दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन सर्च इंजन अल्फाबेट के स्वामित्व वाले Google को पिछले तीन सालों में कुल 8.25 बिलियन यूरो (10 बिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है।
- एंटी-ट्रस्ट जाँच का उद्देश्य बड़ी कंपनियों द्वारा एकाधिकार और एंटीकाम्पिटिटिव प्रयासों को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका को पुनः सुनिश्चित किया जाये क्योंकि अपनी शीर्ष स्थिति को बनाए रखने के लिये ये बड़ी कंपनियाँ प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी व्यवहार का सहारा ले सकती हैं।

बिग टेक कंपनियों की कार्य प्रकृति

- हर किसी के पास इनका उपयोग करने की सुविधा है और भविष्य में उपयोग के लिए इनकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं है क्योंकि लोगों की खपत से उनकी आपूर्ति प्रभावित नहीं होती है।
- इंटरनेट कंपनियां भौगोलिक सीमाओं से प्रतिबंधित हुए बिना काम करती हैं, इसलिए, विभिन्न देश नियामकों द्वारा अकसर अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू करना मुश्किल होता है।
- वैसे तो इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को स्पष्ट रूप से बहिष्कृत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है जिसका लाभ इंटरनेट द्वारा आसानी से उठाते है ताकि उपयोगकर्ताओं को मुफ्त में खोज, नेविगेशन और सामाजिक संपर्क प्रदान किया जा सके, फलस्वरूप, इन सेवाओं को गैर-बहिष्कृत बना दिया गया।

- अर्थशास्त्र में, बहिष्करण सिद्धांत कहता है कि निजी समान का मालिक दूसरों को उस समान के उपयोग से बाहर कर सकता है, जब तक कि वे भुगतान न करें। अर्थात यह उन लोगों को बाहर करता है जो अनिच्छुक हैं, या निजी सामान के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं, लेकिन सार्वजनिक सामानों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें अविभाज्य माना जाता है। ऐसे सामानों की उपलब्धता उन्हें खरीदने के बजाय केवल उनके लाभ प्राप्त करने की होती है।

चुनौतियाँ

- इंटरनेट के व्यावसायीकरण ने गैर-बहिष्करण के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, जिसका अर्थ है कि इंटरनेट फर्मों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत सूचनाओं का सूक्ष्म व्यापार होगा। इन कंपनियों द्वारा लोगों के डेटा के अनैतिक संग्रह और प्रसंस्करण तथा उन पर कुछ विशेष उत्पादों को थोपकर बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत किया गया है।
- चूँकि सार्वजनिक वस्तुओं के वित्तपोषण को सरकार द्वारा अपने राजस्व से कवर किया जाता है, मोटे तौर पर कर-दाताओं के पैसे के माध्यम से, जबकि निजी कंपनियों को अपनी सेवाओं को निःशुल्क प्रदान करने की लागत को कवर करने के लिए मुद्रीकरण मॉडल रखने की आवश्यकता होती है।
- इसलिए सेवाओं के मुक्त प्रावधान को कवर करने के लिए, इंटरनेट कंपनियों ने विमुद्रीकरण उद्देश्यों के लिए अपने उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी के लिए व्यक्तिगत विज्ञापनों और तीसरे पक्ष के साथ साझाकरण का सहारा लिया है।
- जैसे-जैसे अधिक उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त हुई, उन्होंने अधिक सामग्री, सूचना और सेवाओं का उपयोग किया। वेबसाइटों के विकास और सुधार ने अधिक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ जुड़ने और व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। इससे इंटरनेट सेवा में ट्रैफिक वृद्धि का अनुभव किया गया , जिससे नेटवर्क प्रभाव उत्पन्न हुआ।
- नेटवर्क प्रभाव एक ऐसी घटना है जिससे लोगों या प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि होती है जो एक अच्छी सेवा के मूल्य में सुधार करते हैं। इंटरनेट नेटवर्क प्रभाव का एक उदाहरण है।
- इसलिए, इन इंटरनेट प्लेटफॉर्मों को बाजार में बढ़ती हिस्सेदारी के लिए एक बढ़ते ग्राहक आधार और आकांक्षा की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप कुछ कंपनियों के पास ही उनके परिभाषित बाजारों में एकाधिकार हो जाता है।
- हालाँकि, नेटवर्क प्रभाव एक बहुत बड़ा उपभोक्ता अधिशेष भी उत्पन्न करते हैं।
- इंटरनेट फर्म वर्तमान समय में जीवन का एक आंतरिक हिस्सा बन गई हैं, उदाहरण के लिए-Google मानचित्र, विभिन्न स्थानों के लिए हमारे दिन-प्रतिदिन के आवागमन में गतिशीलता का एक अनिवार्य घटक है और गूगल मानचित्र एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) का उपयोग लगभग सभी लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।
- गूगल सर्च, इंटरनेट पर किसी भी जानकारी तक पहुंच का पर्याय बन गई है।
- इसके अलावा गूगल स्कॉलर, शिक्षाविदों के लिए प्रासंगिक अनुसंधान कलाकृतियों का पता लगाने के लिए एक आवश्यक उपकरण है।
- वहीं Facebook API का उपयोग लगभग सभी फर्मों द्वारा विज्ञापन के लिए किया जा रहा है।
- इसलिए नीति निर्माताओं के सामने यह एक बहुत कठिन चुनौती है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से साबित करना आसान काम नहीं है कि फर्म अपनी एकाधिकार शक्ति के दुरुपयोग कर रहे हैं।

आगे की राह

- वर्तमान मुद्दा सिर्फ सरकारों और नियामकों की जिम्मेदारी का नहीं है, इंटरनेट कंपनियों पर भी है कि वे अपने व्यवसायों के संचालन में मूल नैतिक सिद्धांतों का पालन करें। हालाँकि विश्व भर की सरकारों द्वारा उपभोक्ताओं के गोपनीयता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये कड़े सुरक्षा कानून लागू किये गए हैं। जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिये कुछ बुनियादी और आवश्यक डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयता प्रावधानों का पालन करने की अनिवार्यता निर्धारित की गई है और अब आवश्यकता इनके उचित क्रियान्वयन की है।
- उपभोक्ताओं और छोटे प्रतिस्पर्धी फर्मों के हितों को चोट पहुँचाए बिना उत्पादों और सेवाओं के नियंत्रित विस्तार से सम्बंधित मुद्दों को कम करने के लिए इन फर्मों द्वारा भी प्रयास किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

प्र. क्या बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के एकाधिकार से उत्पन्न चुनौतियों को समाप्त करने के लिए नीति निर्माताओं के लिए नियामकीय ढाँचे की आवश्यकता है? चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 भारत का आर्कटिक मसौदा नीति

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत ने अपना आर्कटिक मसौदा नीति जारी किया है। यह मसौदा नीति सतत पर्यटन, वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्कटिक क्षेत्र में गैस और खनिज तेल की खोज का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

2. आर्कटिक मसौदा नीति के मुख्य पांच स्तंभ

- विज्ञान और अनुसंधान
- आर्थिक और मानव विकास
- परिवहन और कनेक्टिविटी
- शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- राष्ट्रीय क्षमता निर्माण

3. उद्देश्य

- यह उन गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को भी सूचीबद्ध करता है जो भारत आर्कटिक में आर्थिक, राजनयिक और वैज्ञानिक गतिविधियों सहित आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता है। इसके अतिरिक्त आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, सतत पर्यटन और खनिज तेल एवं गैस की खोज का विस्तार करना भारत का लक्ष्य है।
- मसौदे के अनुसार आर्कटिक अनुसंधान भारतीय मानसून का अवलोकन करने के साथ हिमालय के ग्लेशियरों की पिघलने की दर का अध्ययन करने में भारत के वैज्ञानिक समुदाय की मदद करेगा।
- भारत वर्ष 2013 में पहली बार आर्कटिक काउंसिल में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। वर्ष 2018 में पांच साल के कार्यकाल के लिए भारत की सदस्यता का नवीनीकरण किया गया।

4. आर्कटिक क्षेत्र में भारत के अन्वेषण

- भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक के लिए अपना पहला वैज्ञानिक अभियान लांच किया था।
- भारत ने नॉर्वे के स्विट्सवर्ग में अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस में एक अनुसंधान केंद्र 'हिमाद्री' की स्थापना की थी।
- इसके अलावा, 2007 के बाद से, भारत ने आर्कटिक में 13 अभियान भेजे हैं और भारत 23 सक्रिय परियोजनाओं का संचालन कर रहा है।
- राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के अनुसार भारत हर साल गर्मी और सर्दी में आर्कटिक में हिमनद, हाइड्रोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और पर्यावरण संबंधी अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की टीमों को भेज रहा है। इन अभियानों में देश के विभिन्न संस्थानों, संगठनों और विश्वविद्यालयों के अनेक वैज्ञानिक भाग लेते हैं।

5. महत्व

- आर्कटिक क्षेत्र और आर्कटिक महासागर का भारत के लिये विशेष महत्त्व है, क्योंकि ध्रुवीय पर्यावरणीय प्रक्रिया और भारतीय मानसून के मध्य गहरा सम्बन्ध है। आर्कटिक महासागर भारतीय मानसूनी पवनों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था मूलत: कृषि पर निर्भर है और भारतीय कृषि मानसून पर। ऐसे में आर्कटिक में किये जा रहे वातावरणीय शोध जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं में बदलाव तथा भारतीय उपमहाद्वीप पर वायुमण्डलीय प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझने में बहुत ही लाभकारी साबित हो सकते हैं।
- आर्कटिक में होने वाले प्रत्येक प्राकृतिक परिवर्तन का असर पूरे विश्व की प्रकृति पर पड़ता है। ऐसे में आर्कटिक क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किये जा रहे विविध शोधकार्य न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि से भी प्रासंगिक हैं। भारतीय वैज्ञानिक आर्कटिक के माध्यम से प्रकृति में हो रहे जलवायुवीय परिवर्तनों और भूमण्डलीय तापन व महासागरीय प्रवृत्तियों का निरन्तर अध्ययन कर रहे हैं। वे इन पर्यवेक्षणों का उपयोग कुछ ऐसे पर्यावरणीय प्रादर्शों को तैयार करने में कर रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर जटिल, परिवर्तित पर्यावरण को समझने, उसके स्पष्टीकरण एवं आवश्यक पूर्वानुमानों को लगाने में सहायता मिल सके।

02 आकाशगंगा में पराबैंगनी तारों की पहचान

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के पहले बहुल तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष उपग्रह (Multi-Wavelength Space Satellite) एस्ट्रोसैट (Astrosat) ने मिल्की वे गैलेक्सी (Milky Way galaxy) में एक विशाल गोलाकार तारा समूह (Globular Cluster) NGC 2808 में दुर्लभ गर्म पराबैंगनी (Ultra Violet-UV) तारों को चिह्नित किया है। ये ऐसे तारों के समूह हैं जो ब्रह्माण्ड में बहुत ही कम देखे गए हैं। इस तारापुंज को ब्रह्माण्ड का डायनासोर (Dinosaur of Universe) कहा गया है।
- भारतीय तारा भौतिकी संस्थान (आईआईए), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों की टीम ने इन सितारों को, एस्ट्रोसैट का उपयोग करते हुए कैप्चर किया है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2020 में, एस्ट्रोसैट ने अपनी कक्षा में पाँच साल पूरे किए हैं।

2. प्रमुख बिन्दु

- भारत के विज्ञान और तकनीकी विभाग के अनुसार इस तारा समूह में बहुत कम पाए जाने वाले ऐसे तारे हैं जो गर्म पराबैंगनी विकरणों से चमकते हैं। इन तारों का केंद्र एक तरह से पूरा खुला हुआ है जिससे वे बहुत ही गर्म तारे बन गए हैं।
- ये तारे सूर्य जैसे तारों के अंतिम अवस्था में हैं। फिर भी अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन तारों का जीवन कैसे समाप्त होता है क्योंकि इनमें से बहुत से तारे अभी अपने शुरुआती दौर में अवलोकित नहीं किए जा सके हैं जो कि उनके अध्ययन के लिए बहुत अहम है।
- पुराने गोलाकार तारापुंजों को ब्रह्माण्ड का डायनासोर कहा जाता है। ये खगोलविदो के लिए बहुत ही विशेष किस्म की लैबोरेटरी मानी जाती हैं जहां वे तारों के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते है। इसके लिए अल्ट्रावॉयलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरें बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं।
- क्लस्टर की शानदार अल्ट्रावॉयलेट (यूवी) छवियों के उपयोग से वैज्ञानिक अपेक्षाकृत ठंडे रेड जाइंट एवं अन्य तारों और गर्म पराबैंगनी-चमकीले तारों में अंतर करते हैं। इस अध्ययन के निष्कर्षों को 'द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल' शोध पत्रिका में प्रकाशन के लिए स्वीकृत किया गया है।
- वैज्ञानिकों ने यूवीआईटी डेटा को दुनिया की अन्य प्रमुख दूरबीनों से प्राप्त डेटा से जोड़कर समायोजित रूप से पेश किया है। इस दौरान हबल स्पेस टेलीस्कोप और गैया (Gaia) टेलीस्कोप जैसे अन्य अंतरिक्ष मिशनों के साथ-साथ जमीन पर आधारित ऑप्टिकल अवलोकनों से प्राप्त तथ्यों का इस शोध में उपयोग किया गया है।
- इनमें से एक पराबैंगनी प्रकाश से चमकने वाला तारे को सूर्य से तीन हजार गुना अधिक चमकीला पाया गया है, जिसकी सतह का तापमान लगभग एक लाख केल्विन है। इन तारों के गुणों को केंद्र में रखकर वैज्ञानिक इनके जन्म एवं विकासक्रम को समझने का प्रयास कर रहे हैं।

3. NGC 2808

- इस क्लस्टर के बारे में कहा जाता है कि इसमें सितारों की पाँच पीढ़ियां होती हैं।
- अध्ययन में पाया गया कि कि ज्यादातर तारे हॉरिजोंटल ब्रांच तारों वाली सौर अवस्था से निकले हैं जिसमें बाहरी परत नहीं के बराबर होती है। इसी वजह से तारे के जीवन की अंतिम प्रमुख अवस्था से नहीं गुजरते हैं जिसे एसिम्प्टोटिक ज्वाइंट अवस्था कहते हैं। वे सीधी ही मृत अवशेष या सफेद बौने तारे बन जाते हैं। एस्ट्रोसैट के जरिए अब तक 800 खगोलीय स्रोतों से 1166 अवलोकन किए हैं।

4. एस्ट्रोसैट

- एस्ट्रोसैट भारत की बहु-तरंगदैर्ध्यो दूरबीन है। इसे इसरो द्वारा वर्ष 2015 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (श्रीहरिकोटा) से PSLV द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन है।

5. भारतीय तारा भौतिकी संस्थान

- भारतीय ताराभौतिकी संस्थान देश का एक प्रमुख संस्थान है, जो खगोल ताराभौतिकी एवं संबंधित भौतिकी में शोधकार्य को समर्पित है। इस संस्थान का मुख्यालय कोरमंगला, बेंगलूर में है।

03 अरुणाचल में चीन द्वारा बसाये गांव से बढ़ती चिंताएँ

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में सेटेलाइट से ली गई एक तस्वीर से पता चला है कि चीन ने अरूणाचल प्रदेश की सीमा पर एक गाँव का निर्माण किया है। यह गाँव भारतीय सीमा के अंदर बनाया गया है। इस गांव में करीब 101 घर भी बनाए गए हैं। यह गांव अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक भारतीय सीमा के करीब 4.5 किमी अंदर स्थित है। इस गांव को त्सारी चू क्षेत्र में बसाया गया है। यह गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है।

2. प्रमुख बिन्दु

- तस्वीरों के विश्लेषण के बाद विशेषज्ञों ने कहा है कि उक्त गांव भारतीय सीमा में करीब साढ़े चार किलोमीटर भीतर बसाया गया है। इस नई जानकारी ने खासकर पूर्वोत्तर सीमा पर भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उस गांव के अरुणाचल के अपर सुबनसिरी जिले में त्सारी नदी के किनारे होने का दावा किया गया है। वह इलाका लंबे अरसे से भारत और चीन के बीच विवादित रहा है और वहां कई बार दोनों देशों की सेना के बीच हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं।
- विशेषज्ञों ने 26 अगस्त 2019 को ली गई सेटेलाइट तस्वीरों से ताजा तस्वीर के मिलान के बाद कहा है कि उक्त गांव एक साल के भीतर बसाया गया है।
- विश्लेषकों का मानना है कि चीन ने अपर सुबनसिरी जिले में भारतीय इलाके में करीब 70 किलोमीटर तक अतिक्रमण कर लिया है। अब नया गांव बसाना भारत के लिए बेहद चिंता की बात है। इससे सीमा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।
- चीन ने इस गांव का ऐसे समय पर निर्माण किया है जब लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने हैं। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है।

3. चीन की मंशा

- चीन बीते कुछ बरसों से खासकर पूर्वोत्तर सीमा पर तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। इनमें सड़क, ब्रिज, बांध और रेलवे लाइन शामिल हैं।
- वैसे, चीन पहले भी सीमावर्ती इलाकों में सक्रियता दिखाता रहा है। लेकिन बीते साल गलवान घाटी में विवाद के बाद उसने खासकर पूर्वोत्तर सीमा पर अपनी गतिविधियां काफी तेज कर दी हैं। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बनाने के फैसला किया गया है, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं।
- अब अपनी नई रणनीति के तहत वह इलाके में एक नई रेलवे परियोजना पूरा करने की तैयारी में है। इससे अरुणाचल प्रदेश सीमा तक उसकी पहुंच काफी आसान हो जाएगी। चीन की यह परियोजना भारत के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। चीन ने हाल में ही सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एक रेलवे ब्रिज का काम पूरा कर लिया है।
- अरुणाचल में सियांग कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 525 मीटर लंबा यह ब्रिज नियंत्रण रेखा से महज 30 किलोमीटर दूर है। यह ब्रिज दरअसल 435 किलोमीटर लंबी ल्हासा-निंग्ची (लिंझी) रेलवे परियोजना का हिस्सा है। सामरिक और रणनीतिक रूप से सिचुआन-तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण काफी अहम है। यह रेलवे लाइन दक्षिण-पश्चिमी प्रांत सिचुआन की राजधानी चेंग्डू से शुरू होकर तिब्बत के लिंझी तक जाएगी। लिंझी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से एकदम करीब है।

4. भारत के लिए चिंता की बात

- चीनी गांव के पास भारत की कोई सड़क नहीं है और न ही कोई आधारभूत ढांचा है। इससे पहले नवंबर 2020 में बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गावो ने लोकसभा में बताया था कि अरुणाचल राज्य में चीन की घुसपैठ बढ़ रही है । उन्होंने ऊपरी सुबनसिरी जिले का विशेष रूप से उल्लेख किया था। सांसद तापिर गावो के अनुसार चीन सुबनसिरी जिले में सीमा में 60 से 70 किमी अंदर घुस आया है।

5. निष्कर्ष

- भारत भी सीमावर्ती इलाके में बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। भारत ने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों के अलावा ब्रिज बनाए हैं। भारत को भी जवाबी रणनीति बना कर ठोस कार्रवाई करनी होगी। भारत का मानना है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

04 IRDAI ने दिया Traffic Violation Premium का सुझाव

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में इंश्योरेंस रेगुलेटर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के एक वर्किंग ग्रुप ने यातायात उल्लंघन प्रीमियम (Traffic Violation Premium) का सुझाव दिया है, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को अपने वाहन के इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।

2. परिचय

- ज्ञातव्य है कि IRDAI के वर्किंग ग्रुप ने सुझाव दिया है कि मोटर इंश्योरेंस में स्वयं क्षति की भरपाई, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ दूसरे तरह के बीमा प्रीमियम अर्थात Traffic Violation Premium की भी शुरुआत की जाए।
- IRDAI ने इस वर्किंग ग्रुप के ड्राफ्ट में की गई इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से 1 फरवरी 2021 तक जरुरी सुझाव मांगे हैं।

3. मुख्य बिंदु

- इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की फ्रिक्वेंसी और उसकी गंभीरता के कैलकुलेशन के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए।
- इसके तहत अधिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को Traffic Violation Premium से लिंक किया जाए अर्थात आप जितनी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे, खराब ड्राइविंग करेंगे, आपको उतना अधिक प्रीमियम देना होगा, साथ ही इस प्रीमियम का भुगतान ड्राइवर के बदले वाहन मालिक को करना होगा।
- इन सिफारिशों के मुताबिक, Traffic Violation Premium का निर्धारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पार्किंग करने जैसे अलग अलग गंभीरता वाले उल्लंघनों से तय होगा।
- वाहन को बेचने के बाद Traffic Violation Premium जीरो से शुरू होगा, क्योंकि अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अधिक प्रीमियम नए ऑनर को देना होगा।
- प्रस्ताव के अनुसार यह प्रीमियम वाहन के भविष्य से संबंधित होगा किसी नए वाहन के संबंध में यह शून्य होगा।

4. योजना का क्रियान्वयन

- दिल्ली के एनसीटी और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की ट्रैफिक पुलिस पहले से ही कुछ समय के लिए वाहनों के ट्रैफिक उल्लंघन के डेटा एकत्र कर रही है।
- IIB तुरंत इस डेटा को लेने और अपने डेटाबेस में वाहनों के बीमा रिकॉर्ड के साथ एकीकृत करने की व्यवस्था कर सकता है और जब भी यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाता है तब IIB और बीमाकर्ता के पास पहले से ही यातायात उल्लंघन के डेटा का एक उचित विवरण होगा।
- सरकार ने पहले से ही संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 में विभिन्न प्रकार के यातायात उल्लंघनों पर भारी जुर्माना लगाया है।
- इसके अलावा, भारत सरकार महानगर और स्मार्ट शहरों में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।
- गौरतलब है कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्ट 2018 के अनुसार, भारत में 1.51 लाख नागरिकों में से 4.67 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से अधिकतर लोगों को अपनी जान गवांनी पड़ी।
- विश्व सड़क सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 में 199 देशों में सड़क दुर्घटना से मृत्यु के मामले में भारत पहले स्थान पर था।

05 एनबीएफसी के विनियमन के लिये 4- टियर स्ट्रक्चर

1. चर्चा का कारण

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के विनियमन की योजना बनाई है।

2. परिचय

- पिछले एक-दो सालों से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में गड़बड़ियों के बाद केंद्रीय बैंक के लिए यह चिंता का विषय बन गया है।
- मौजूदा समय में देश में करीब 10 हजार एनबीएफसी हैं, लेकिन उनमें से मुश्किल से दो दर्जन ही ऐसे हैं, जो वित्तीय रूप से मजबूत हैं। लॉकडाउन की वजह से देश में आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने की वजह से एनबीएफसी को काम करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
- बाजार में कर्ज की मांग न होने के वजह से एनबीएफसी का व्यवसाय पिछले काफी दिनों से एकदम सुस्त पड़ा हुआ था, जिसके चलते हाल ही में आरबीआई ने तीन एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया था और छह एनबीएफसी ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया।
- आरबीआई शीर्ष 50 एनबीएफसी पर करीब से नजर रखेगा और उनका ऑडिट बैंकों की तरह होगा।
- ऊपरी तथा सबसे शीर्ष स्तर की एनबीएफसी की सख्ती से जांच-परख की जाएगी क्योंकि उनमें गड़बड़ी होने से पूरे वित्तीय तंत्र पर असर पड़ता है। 2018 में IL & FS के मामले में ऐसा देखा जा चुका है।

3. NBFCs का प्रस्तावित वर्गीकरण

- भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के नियमन की चार स्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया है।
- इसमें आकार-प्रकार के हिसाब से कंपनियों के लिए नियम हल्के या ज्यादा कड़े रखे जाएंगे। रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिचर्चा पत्र में एनबीएफसी कंपनियों को चार स्तरों प्रथमिक, मध्यम, उच्च और शीर्ष श्रेणी में रखा जाएगा।
- यह वर्गीकरण आकार, कंपनी पर कर्ज के अनुपात, परस्पर जुड़ाव, प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना, कारोबार की जटिलताओं और प्रकृति जैसे कारकों के आधार पर किया जाएगा।

प्राथमिक

- प्राथमिक स्तर की NBFCs को एनबीएफसी-बेस लेयर (NBFC&BL) के रूप में जाना जाएगा।
- इस लेयर की NBFCs के लिये कम-से-कम विनियामक हस्तक्षेप को मंजूरी प्रदान की गई है।
- इस स्तर में 1,000 करोड़ रुपये तक संपत्ति वाली एनबीएफसी होंगी और अधिकतर इकाइयां इसी में आ जाएंगी। इस स्तर के लिए नियामक व्यवस्था कुछ नरम होंगे।

मध्यम स्तर

- मध्यम स्तर में NBFCs को NBFC- मिडिल लेयर (NBFC-ML) के रूप में जाना जाएगा।
- इस लेयर के लिये नियामक व्यवस्था कुछ सख्त होगी।

उच्च स्तर

- इसे NBFC-अपर लेयर के रूप में जाना जाएगा जो एक नई नियामक संरचना को आमंत्रित करेगा।
- यह लेयर NBFCs द्वारा संचालित होगी हालाँकि वर्तमान में इस लेयर के समान कोई लेयर नही है अतः यह विनियमन के लिये एक नई लेयर होगी। इस लेयर में शामिल होने वाली NBFCs के लिये विनियामक ढांचा बैंक जैसा ही होगा।

शीर्ष स्तर

- ये NBFCs अपर लेयर के शीर्ष पर एक अलग समूह के रूप में स्थापित होंगी। शीर्ष तब तक रिक्त रहेगी जब तक कि पर्यवेक्षक विशिष्ट NBFCs पर विचार नहीं करेंगे।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो,
- इसका मुख्य कारोबार उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों/स्टॉक/ बांड्स/ डिबेंचरों/प्रतिभूतियों, पट्टा कारोबार , बीमा कारोबार, चिट संबंधी कारोबार में निवेश करना, तथा किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत एकमुश्त रूप से अथवा किस्तों में जमाराशियां प्राप्त करना है।
- किंतु, किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ऐसी कोई संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य कारोबार कृषि, औद्योगिक, व्यापार संबंधी गतिविधियां हैं अथवा अचल संपत्ति का विक्रय/क्रय/निर्माण करना है।

4. आगे की राह

- मौजूदा एनबीएफसी को इनके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा जहाँ एनबीएफसी के कॉर्पोरेट संचालन हेतु उच्च गुणवत्ता वाले मानकों का पालन करना होगा।
- किसी एक इकाई का दबदबा रोकने के लिए उन्हें मालिकाना हक से जुड़ी संरचना में भी बदलाव करना होगा। आंतरिक बोर्ड से मंजूरी नीति के आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों में ऋण आवंटन भी दुरुस्त करना होगा।

06 राष्ट्रीय बालिका दिवस

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में पूरे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है।
- इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा की गई थी।

2. राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य

- इसका लक्ष्य राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने के मुख्य रूप से तीन उद्देश्य हैं-
  - बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ ही बालिकाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य व पोषण के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाना है।
  - विभिन्न अत्याचारों और असमानताओं के बारे में बात करना, जो लड़कियों को अपने दैनिक जीवन में सामना करना पड़ता है
  - लड़कियों के शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्व समझाने तथा इसे बढ़ावा देने हेतु

3. सरकारी प्रयास

- भारत सरकार ने ऐसी कई पहल की है, जो शिक्षा तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और लिंग संवेदनशीलता में सुधार सहित बालिकाओं के सशक्तिकरण पर केन्द्रित हैं।
- शिक्षा, खेल, कौशल विकास मंत्रालय जैसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बालिकाओं की प्रगति और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहल और कार्यक्रम लागू किए हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)- 2020 में बालिकाओं के विकास पर केन्द्रित 'लिंग समावेशन कोष' (Gender Inclusion Fund) पेश किया गया है।
- एनईपी में कहा गया है कि भारत सरकार सभी बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए "लिंग समावेशन कोष" की स्थापना करेगी।
- इस कोष के माध्यम से स्कूली पढ़ाई में बालिकाओं का 100 प्रतिशत नामांकन और उच्च शिक्षा में एक रिकॉर्ड भागीदारी दर, सभी स्तरों पर लिंग असमानता में कमी, लिंग समानता का पालन और समाज में समावेशन तथा सकारात्मक नागरिक संवाद के माध्यम से बालिकाओं की नेतृत्व क्षमता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
- स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना 'समग्र शिक्षा' का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा पर केन्द्रित कई कदम उठाए गए हैं।
- स्कूली शिक्षा में हर स्तर पर लिंग और सामाजिक श्रेणी से जुड़ी खामियों को दूर करना 'समग्र शिक्षा' के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

4. योजनाओं का लाभ

- खेलों में महिलाओं के लिए जागरूकता का माहौल तैयार किया और खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए बालिकाओं को प्रेरित किया गया साथ ही खेलो इंडिया योजना के तहत खेल गतिविधियों में बालिकाओं और महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं को सीमित किया गया है जिससे 2018 से 2020 के बीच खेलो इंडिया गेम्स में महिलाओं की भागीदारी में 161 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
- इसी प्रकार कौशल विकास मंत्रालय द्वारा भारत में महिलाओं को कुशल बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) में, महिला अप्रेंटिसों की भागीदारी अगस्त, 2016 की 4 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर, 2020 में बढ़कर 12 प्रतिशत हो गई है।

07 द इनइक्वैलिटी वायरस

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में ऑक्सफैम (Oxfam) द्वारा 'द इनइक्वैलिटी वायरस' (The Inequality Virus) नाम से जारी की गयी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी ने भारत समेत दुनिया भर में मौजूदा असमानताओं को बढ़ाने का काम किया है।

2. इनइक्वैलिटी वायरस रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु

- इस रिपोर्ट के अनुसार फारचून पत्रिका में शामिल शीर्ष 1,000 अरबपतियों को अपनी पूर्व महामारी की स्थिति में वापस आने में सिर्फ नौ महीने का समय लगा, जबकि दुनिया के सबसे गरीब लोगों को अपनी महामारी पूर्व स्थिति में वापस आने में इससे 14 गुना अधिक अर्थात एक दशक से अधिक समय लग सकता है।
- संकट शुरू होने के बाद से 10 सबसे अमीर अरबपतियों की संपत्ति में जितनी वृद्धि हुई है, वह पृथ्वी पर वाइरस के कारण गरीबी का सामना करने वालों और सभी के लिए COVID-19 वैक्सीन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है।
- इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2020 की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि विश्व स्तर पर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से अधिक था, और सबसे प्रभावित भी महिलाएं ही हुई हैं। यदि इस क्षेत्रों में पुरुषों के समान महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो लगभग 112 मिलियन महिलाएं अपनी आय या नौकरी खोने के जोखिम से बच सकती थी।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजील में, श्वेत लोगों की तुलना में अश्वेत लोगों की कोविड-19 से मरने की संभावना 40% अधिक है। यदि उनकी मृत्यु दर श्वेत लोगों के बराबर होती, तो जून 2020 तक 9,200 से अधिक अश्वेत व्यक्ति अभी जीवित होते।
- इसी प्रकार अमेरिका में, लैटिन और अश्वेत व्यक्तियों की श्वेतों की तुलना में कोविड-19 से मरने की अधिक संभावना है।यदि उनकी मृत्यु दर श्वेत लोगों के समान होती, तो दिसंबर 2020 तक, लगभग 22,000 लैटिन और अश्वेत व्यक्ति अभी भी जीवित होते।
- इस रिपोर्ट में विश्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि यदि सभी देश अभी से कोविड-19 के कारण बढ़ी असमानता को कम करने के लिए कार्य करते हैं तो इसे केवल तीन वर्षों में पूर्व-संकट के स्तर पर लाया जा सकता है।

3. रिपोर्ट में भारत की स्थिति

- द इनइक्वैलिटी वायरस' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था संकुचन से लाखों भारतीयों की नौकरियां चली गई, लेकिन अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में लॉकडाउन के दौरान 35 % और वर्ष 2009 के स्तर से 90% की बढ़ोतरी हुई है।
- भारत के 100 अरबपतियों की संपत्ति में मार्च 2020 के बाद से 1297822 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। यह संपत्ति 138 मिलियन सबसे गरीब भारतीयों में से प्रत्येक को 94045 रुपये का चेक देने के लिए पर्याप्त है।
- महामारी के दौरान शीर्ष 11 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में हुई वृद्धि, 10 वर्ष के लिए नरेगा में होने वाले खर्च अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय के 10 वर्ष के बजट के बराबर है।
- रिपोर्ट में महामारी के कारण भारत में गरीब बच्चों के सामने उत्पन्न स्कूली शिक्षा की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि केवल 4 फीसदी ग्रामीण परिवारों के पास ही कंप्यूटर और 15 फीसदी से कम ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे गरीब 20 फीसदी में से केवल 6 फीसदी लोगों की ही निजी स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच है, जबकि उच्च वर्ग की 20 फीसदी आबादी में यह आंकड़ा 93.4 फीसदी है।
- भारत की 59.6 फीसदी आबादी एक कमरे से भी कम जगह में रहती है, ऐसी परिस्थितियों में बहुत बड़ी आबादी के लिए हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे उपायों को अपनाना संभव नहीं है।
- रिपोर्ट के अनुसार, कोविड के दौरान गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं को अकसर स्वास्थ्य मदद नहीं मिल पायी क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को कोविड जांच सुविधाओं और अस्पतालों में बदल दिया गया था।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 भारत का आर्कटिक मसौदा नीति

प्र. आर्कटिक मसौदा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आर्कटिक मसौदा नीति का उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र में खनिज तेल एवं गैस की खोज तथा वैज्ञानिक अनुसंधान का विस्तार करना है।
2. 2013 में भारत आर्कटिक काउंसिल में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था।

उपरोक्त कथन में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1
(c) केवल 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्या : हिमाद्री भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान केन्द्र है, जिसे 2008 में स्थापित किया गया था। भारत ने आर्कटिक क्षेत्रों में 13 अभियान भेजे हैं और 23 सक्रिय परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। इन परियोजनाओं में देश के विभिन्न संस्थानों, संगठनों और विश्वविद्यालयों के अनेक वैज्ञानिकों की भागीदारी है। इस संदर्भ में दोनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

02 आकाशगंगा में पराबैंगनी तारों की पहचान

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत के उपग्रह एस्ट्रोसैट ने मिल्की वे गैलेक्सी में एक दुलर्भ गर्म पराबैंगनी तारों को चिन्हित किया है।
2. एस्ट्रोसैट भारत की बहु-तरंगदैर्ध्यों वाली दूरबीन है, जिसे इसरो द्वारा 2018 में लांच किया गया था।
3. भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कोरमंगला (बेंगलूर) में अवस्थित है।

उपरोक्त कथन में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्या : एस्ट्रोसैट को इसरो द्वारा 2015 में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से PSLV के माध्यम से लांच किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में हुआ था। इस संस्था का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित तकनीकी उपलब्ध कराना है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, अतः उत्तर (a) होगा।

03 अरुणाचल में चीन द्वारा बसाये गांव से बढ़ती चिंताएँ

प्र. अरूणाचल प्रदेश में चीन द्वारा बसाये गये गांव से बढ़ती चिंताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह गांव अरूणाचल प्रदेश में वास्तविक भारतीय सीमा के करीब 4.5 किमी. अदंर सुबनसिरी जिले में स्थित है।
2. चीन पूरे अरूणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (c)

व्याख्या : विशेषज्ञों के अनुसार चीन ने अरूणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में एक गांव बसाकर वहां लगभग 101 घर बनवाए हैं। गौरतलब है कि चीन पूर्वोत्तर सीमा पर तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। इनमें सड़क, ब्रिज, बांध और रेलवे लाइन शामिल हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

04 IRDAI ने दिया Traffic Violation Premium का सुझाव

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 2018 के विश्व सड़क सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 199 देशों में सड़क दुर्घटन से मृत्यु के मामलों में भारत पहले स्थान पर था।
2. इंश्योरेंस विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने यातायात उल्लंघन प्रीमियम को और अधिक करने का सुझाव दिया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1 और 2 दोनों
(c) केवल 1 (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्या : यातायात उल्लंघन प्रीमियम के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को अपने वाहन के इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। विदित हो कि संशोधित मोटन वाहन अधिनियम 2019 में यातायात उल्लंघन पर भी जुर्माना का प्रावधान है। इस तरह कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः उत्तर (b) होगा।

05 एनबीएफसी के विनियमन के लिये 4-टियर स्ट्रक्चर

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी को गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कहा जाता है।
2. एनबीएफसी मुख्य रूप से प्रतिभूतियों स्टॉक्स, बीमा आदि क्षेत्रों में निवेश करती है।
3. एनबीएफसी का संचालन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: एनबीएफसी भारतीय रिजर्व बैंक के देख-रेख में कार्य करती है। देश में लगभग 10 हजार एनबीएफसी हैं। पिछले एक-दो सालों में गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियों से आरबीआई ने तीन एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है और यह एनबीएफसी ने खुद अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। इस संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों सही है अतः उत्तर (b) होगा।

06 राष्ट्रीय बालिका दिवस

प्र. राष्ट्रीय बालिका दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
3. इसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना तथा बालिकाओं के स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण से संबंधित महत्त्व को प्रोत्साहित करना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या : राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरूआत 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गयी थी। विदित हो कि बालिकाओं को सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में 'लैंगिक समावेशन कोष' पेश किया गया। इस प्रकार कथन 2 सही है अतः उत्तर (b) होगा।

07 द इनइक्वैलिटी वायरस

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ऑक्सफैम (OX Fam) ने 'द इनइक्वैलिटी वायरस' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है।
2. 'द इनइक्वैलिटी वायरस' रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण लाखों लोगों की नौकरी चली गई है लेकिन अरबपतियों के संपत्तियों में वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: ऑक्सफैम के रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजील में श्वेत लोगों की तुलना में अश्वेत लोगों की कोविड-19 से मरने की संभावना 40% अधिक है। यदि भारतीय अरबपतियों की स्थिति को देखें तो इनकी सम्पत्तियों में लॉकडाउन के दौरान 35% और वर्ष 2009 से अब तक 90% बढ़ोत्तरी हुई है। इस तरह कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः उत्तर (c)होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 भ्रष्टाचार बोध सूचकांक–2020

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2020 (Corruption Perception Index-2020) को जारी किया गया है।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2020 से जुड़ें प्रमुख बिन्दु

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2020 में 180 देशों में भारत का स्थान छह पायदान फिसलकर 86वें नंबर पर आ गया है। इस वर्ष भारत का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में स्कोर 40 अंक है।
- भारत का स्कोर चीन की तुलना में भी कम है, जिसने 78 के रैंक के साथ 42 का स्कोर किया। वहीं अमेरिका 67 वें, पाकिस्तान 124 वें और नेपाल 117वें स्थान पर हैं।
- सूचकांक में भारत का स्कोर वैश्विक औसत और एशिया-प्रशांत दोनों औसत से नीचे है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब भी भ्रष्टाचार सूचकांक में काफी पीछे है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में भारत, इस सूचकांक में 80वें स्थान पर था, जबकि वर्ष 2018 में 78वें स्थान पर था।

शीर्ष स्थान पर देश:

- न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है।

- सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 स्कोर के साथ 179 वें रैंक के साथ पर सबसे निचले स्थान पर हैं।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perception Index)

- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (सीपीआई), किसी भी देश में सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तर को मापने हेतु जारी किया जाता है।
- इस सूचकांक में शून्य से लेकर 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां शून्य स्कोर वाले देश को सबसे अधिक भ्रष्ट माना जाता है और 100 स्कोर वाले को सबसे कम भ्रष्ट माना जाता है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) के बारे में

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International), ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक स्वतंत्र अन्तरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है, जो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से जुड़े सूचकांक निर्धारित करता है।
- यह संस्था कई रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन होता है।
- इस संगठन के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (Corruption Perceptions Index-CPI), वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट (Global Corruption Report) और रिश्वत भुगतानकर्ता सूचकांक (Bribe Payers Index) प्रकाशित किया जाता है।
- ट्रान्सपैरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अध्यक्ष डेलिया फेरीरा रुबियो है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना 4 मई 1993 को किया गया था।

02 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2020

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हर राज्य में पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी मदद के रोल के आधार पर तैयार की जाती है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में

- टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन काज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव समेत कई संस्थानों की मदद से रिपोर्ट तैयार किया।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- टाटा ट्रस्ट की तरफ से तैयार इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2020 के मुताबिक देश में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में अव्वल है। महाराष्ट्र के बाद इस मामले में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल का नंबर आता है।
- एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा न्याय दे रहे हैं।
- रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में महिला जजों की संख्या महज 29 फीसदी है। हालांकि हाईकोर्ट में महिला जजों का औसत 11 से बढ़कर 13 फीसदी, जबकि सहायक अदालतों में 28 से बढ़कर 30 फीसदी हुआ है।
- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2020 तक राष्ट्रीय स्तर पर 3 पुलिस अधिकारियों में से 1 पद खाली है। एमपी और बिहार में 2 में से 1 अधिकारी का पद खाली है।
- गौरतलब है कि जस्टिस लोकुर के मुताबिक, नेशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रिड के हिसाब से 3.84 करोड़ से ज्यादा मुकदमे जिला अदालतों में लंबित हैं। इसमें सभी हाईकोर्ट में लंबित 47.4 लाख मुकदमे भी जोड़ दें तो यह संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच जाती है। उन्होंने इस हालात से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर न्यायिक सुधार की आवश्यकता जताई है।

अधीनस्थ अदालतों में लंबित प्रकरण

- पांच से दस साल पुराने - 3 लाख 48 हजार 325
- दस से बीस साल पुराने - 75 हजार 034
- बीस से तीस साल पुराने - 4 हजार 390
- तीस साल से ज्यादा पुराने - 567

हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण

- पांच से दस साल पुराने - 88 हजार 431
- दस से बीस साल पुराने - 74 हजार 594
- बीस से तीस साल पुराने - 11 हजार 114
- तीस साल से ज्यादा पुराने - 528

कॉन्स्टेबल का हर 5 में से 1 पद खाली

- राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्स्टेबल का हर 5 में से 1 पद खाली है। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में कॉन्स्टेबलों के 40 फीसदी पद खाली हैं।

पंजाब और महाराष्ट्र की पुलिस रैंकिंग में गिरावट

- पिछले एक साल में पंजाब और महाराष्ट्र पुलिस के रैंकिंग में गिरावट आया हैं जबकि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने छलांग लगाई है। साल 2019 के इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पंजाब जहां तीसरे नंबर पर था वहीं वो इस साल पिछड़कर 12वें स्थान पर आ गया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में पुलिस पर सरकारी खर्च कम हुआ है, पिछले पांच साल में अधिकारियों और कॉन्स्टेबलों की वैकेंसी बढ़ी है। इसके अलावा यहां पुलिस आधुनिकीकरण पर होने वाला खर्च भी कम हुआ है।

03 लिटिल अंडमान द्वीप विजन डॉक्यूमेंट

चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने 'लिटिल अंडमान द्वीप का सतत विकास' के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट (Sustainable Development of Little Andaman Island Vision Document) प्रस्तुत किया है।

विजन डॉक्यूमेंट से जुड़े प्रमुख बिन्दु

- नीति आयोग ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में लिटिल अंडमान द्वीप के लिए एक मेगासिटी प्लान (megacity plan) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह मेगासिटी लिटिल अंडमान द्वीप के 680 वर्ग किमी क्षेत्र में विकसित की जाएगी।
- इसके तहत एक नई ग्रीनफील्ड तटीय शहर (New Greenfield Coastal City) बनाकर तैयार की जाएगी, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Zone) के रूप में विकसित किया जाएगा। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा।
- इसमें अंडरवाटर रिजॉर्ट्स, कसीनो, गोल्फ कोर्स, कन्वेंशन संटर,अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अस्पताल, विशेष वन रिसॉर्ट इत्यादि का भी विकास किया जाएगा।
- नीति आयोग का कहना है कि इस मेगासिटी प्लान से पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का विकास सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त, इसके रणनीतिक महत्व में और इजाफा होगा।
- इस मेगासिटी प्लान से स्थायी और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।

विजन डॉक्यूमेंट प्रस्ताव के समक्ष चुनौतियाँ

- लिटिल अंडमान के लिए, नीति आयोग के इस विजन डॉक्यूमेंट की पर्यावरणविदों द्वारा आलोचना की जा रही है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे लिटिल अंडमान द्वीप को काफी क्षति होगी और यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा।
- सितंबर, 2020 को लिटिल अंडमान के प्रभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest

Officer) ने निम्नलिखित तीन आधारों पर इस विजन डॉक्यूमेंट के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त कीं थीं-

- पारिस्थितिकी संवेदनशीलता (Ecological Fragility)
- स्थानीय अधिकार (Indigenous Rights)
- भूकंप और सुनामी के लिए सुभेद्यता (Vulnerability To Earthquakes And Tsunamis)

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बारे में

- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है, जिसमें छोटे बड़े लगभग 576 द्वीप शामिल हैं। इन द्वीपों को दो प्रमुख द्वीपसमूहों में बाँटा गया है अर्थात् उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 100 चैनल द्वारा एक-दूसरे से अलग होते हैं।
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पूर्व में स्थित अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार देशों से अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी 'बैरन द्वीप' यहीं स्थित है।
- अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पारिस्थितिकी तंत्र में कठोर या चट्टानी प्रवाल की 555 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो पर्यावरणीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं।
- इसके अतिरिक्त, लंबे समय तक मुख्य भूमि से अलगाव के कारण ये द्वीप कई प्रजातियों के उद्‌भव के लिए हॉटस्पॉट बने जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों स्थानिक प्रजातियाँ और उपप्रजातियाँ यहाँ विकसित हुई हैं।

04 'चौरी-चौरा' कांड के 100 वर्ष

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में 'चौरी-चौरा' कांड के 100 वर्ष पुरे होने वाले है एवं इसके उपलक्ष्य में सरकार द्वारा शताब्दी समारोहों और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जोकि 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी, 2022 तक जारी रहेंगे।

पृष्ठभूमि

- उल्लेखनीय है कि सितम्बभर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वमतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्यारय मिलने की कोई संभावना नहीं है इसलिए उन्होंसने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरूआत की गई। यह आंदोलन अत्योत सफल रहा, क्यों कि इसे लाखों भारतीयों का समर्थन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। असहयोग आंदोलन के कारण चौरी-चौरा काण्ड की घटना घटित हुई जिसके उपरांत हिंसा की आशंका के मद्देनजर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।

चौरी-चौरा की घटना

- चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था (वर्तमान में तहसील है), जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिन्दा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरीचौरा काण्ड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणामस्वरूप गांधीजी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आन्दोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस ले लिया था। इस मामले में गोरखपुर के न्यायालय में अब्दुल्ला बनाम सरकार के नाम से मुकदमा दर्ज हुआ। घटना की जांच तत्कालीन डीआईजी सेन को मिली थी।
- बाबा राघव दास के कहने पर मालवीय ने अदालत में क्रांतिकारियों का पक्ष रखा और मृत्युदंड की सजा पाए 114 लोगों में से 95 लोगों की सजा माफ कराई, जबकि 19 क्रांतिकारियों की फांसी की सजा बरकरार रही। फांसी की सजा पाए 19 क्रांतिकारियों की तरफ से दया याचिका दायर हुई, मगर 1 जुलाई 1923 को दया याचिका अस्वीकार कर दी गई। चौरी-चौरा काण्ड के आरोप में देश की अलग-अलग जेलों में बंद 19 क्रांतिकारियों को 2 जुलाई 1923 को फांसी दी गई।

05 मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना (मित्र योजना)

चर्चा में क्यों?

- 2021-22 के केन्द्रीय बजट में सरकार द्वारा कपड़ा उद्योग के संवर्धन हेतु मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क-मित्रा योजना (Mega Investment Textiles Parks-MITRA) योजना की घोषणा की गयी है।

मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क: मित्रा योजना (MITRA) के बारे में

- भारत के कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने 2021-22 के केन्द्रीय बजट में मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क- मित्र (Mega Investment Teñtiles Parks-MITRA) योजना की घोषणा की है।

उद्देश्य

- कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाना,
- बड़े निवेश को आकर्षित करना
- रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना
- निर्यात को बढ़ावा देना

मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क की विशेषताएँ

- यहाँ भारत को निर्यात में विश्व चैम्पियन बनाने के लिए प्लग और प्ले सुविधा के साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना का सृजन प्रस्तावित किया गया है।
- मित्र योजना को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के अतिरिक्त आरंभ किया जायेगा।
- आने वाले तीन वर्षों में ऐसे 7 मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क का निर्माण किया जाना है।

Mega Investment Textiles Parks (MITRA) Scheme

संभावित लाभ

- कपड़ा उद्योग (Textile Sector) कृषि क्षेत्र (agriculture sector) के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता क्षेत्र है। टेक्सटाइल्स निर्यात के मामले में भारत का विश्व में पाँचवाँ स्थान है।
- 5वां सबसे बड़ा निर्यातक होने के बावजूद भी भारत अभी तक इस क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पर रहा है। मित्रा योजना वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने और वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
- भारत में पहले से ही उत्पादन की मात्रा और प्रौद्योगिकीय परिवेश में सुधार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, अब इस प्रकार के समेकित टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से उत्पादन गुणवत्ता के साथ-साथ प्रौद्योगिकीय परिवेश में भी सुधार होगा है।
- मित्र के माध्यम से आधुनिकतम अवसंरचना पर जोर देने से घरेलू निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में समान मौके मिलेंगे और इससे भारत कपड़ा निर्यात में सभी क्षेत्रों में विश्व चैम्पियन बनने के मार्ग पर बढ़ेगा।
- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के साथ मित्र अधिक निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।

कपड़ा उद्योग के संवर्धन हेतु अन्य पहल

- मानव निर्मित वस्त्रों में लगने वाले कच्चे माल की निविष्टियों पर शुल्कों को युक्तिसंगत करने की जरूरत मानते हुए सरकार द्वारा नायलन चौन को पोली-एस्टर और अन्य मानव निर्मित रेशों के बराबरी पर लाने की घोषणा की है।
- सरकार द्वारा कैप्रोलेक्टम, नायलन चिप्स, नायलन फाइबर और धागे पर बीसीडी दर एक समान रूप से पांच प्रतिशत घटाने की घोषणा की गयी है। कपड़ा उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा निर्यात को भी मदद मिलेगी।

06 ऑपरेशन ग्रीन योजना

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में 22 और उत्पादों को ऑपरेशन ग्रीन योजना- 'TOPS' के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है।
- कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्य वृद्धि और उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021 में ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ते हुए इसमें 22 नए उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की है। वर्तमान में ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत केवल टमाटर, प्याज, आलू (TOPs) ही शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

- पिछले वर्ष खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के तहत पायलट परियोजना के तौर पर ऑपरेशन ग्रीन योजना को छः माह के लिए टमाटर, प्याज और आलू (TOP) से आगे बढ़ाकर सभी फलों और सब्जियों (TOTAL) तक विस्तारित किया था।
- जुलाई 2020 में भी सरकार ने किसानों और प्रसंस्करण-कर्ताओं को मौजूदा ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत 18 अन्य फलों और सब्जियों का अधिशेष उत्पादन क्षेत्रों से प्रमुख उपभोग

केंद्रों तक परिवहन और भंडारण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ देने की घोषणा की थी।

- सरकार के इस हस्तक्षेप का उद्देश्य फल और सब्जियों के उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण बिना भाव की बिक्री से बचाना और हार्वेस्टिंग के बाद के नुकसान को कम करना है।

ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में

- कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओज), कृषि लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन के प्रोत्साहन के लिए केंद्रीय बजट 2018-19 के बजट भाषण में "ऑपरेशन फ्लड" की तर्ज पर 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक नई स्कीम "ऑपरेशन ग्रीन्स" की घोषणा की गई थी। इसके बाद, मंत्रालय ने टमाटर, प्याज एवं आलू (टॉप) की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए एक स्कीम का निरूपण किया है।
- हाल ही में संसद में पारित हुए बजट 2021 में ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ते हुये इसमें 22 नए उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की है।

ऑपरेशन ग्रीन योजना के उद्देश्य

- टॉप उत्पादन क्लस्टरों और उनके एफपीओज को सुदृढ़ करने और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेप द्वारा टॉप का उत्पादन करने वाले किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि।
- टॉप क्लस्टरों में यथोचित उत्पादन योजना और दोहरे उपयोग वाली किस्मों को शामिल करते हुए उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण।
- खेत स्तर पर अवसंरचना के सृजन, उपयुक्त कृषि-लॉजिस्टिक्स के विकास, यथोचित भंडारण क्षमता केसृजन तथा उपभोग केंद्रों से जुड़ान द्वारा फसलोत्तर हानियों में कमी ।
- उत्पादन क्लस्टरों के साथ सुदृढ़ लिंकेज सहित टॉप की मूल्य श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता एवं मूल्यवर्धन में बढ़ोत्तरी।
- मांग और आपूर्ति तथा टॉप फसलों के मूल्य के संबंध में सही आंकड़े इकट्ठा करने और उन्हें समानुक्रमित करने के लिए एक बाजार आसूचना नेटवर्क की स्थापना।

ऑपरेशन ग्रीन योजना के विस्तार से संबंधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

पात्र फसलें:

- फल- आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, नींबू, अन्नानास, अनार, कटहल, मौसम्बी, संतरा, किन्नू, सेब, बादाम, आंवला, पैशन फ्रूट, नाशपाती, शकरकंद, चीकू;
- सब्जियाँ- फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च (हरा), भिंडी, प्याज, आलू, टमाटर, बड़ी इलाइचि, कद्दू, अदरक, गोभी, हल्दी (सूखी)।

07 जल जीवन मिशन (शहरी)

चर्चा में क्यों?

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के केंद्रीय बजट में शहरी क्षेत्रों के लिए एक सार्वभौमिक जल आपूर्ति योजना- जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की है।

जल जीवन मिशन (शहरी) योजना के प्रमुख बिन्दु

- इस योजना की कार्यान्वयन अवधि पाँच वर्ष रखी गयी है।
- इसके तहत 2,87,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
- इसका सार्वभौमिक जल आपूर्ति योजना का उद्देश्य सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरों तक नल-जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना है।
- यह योजना 2021 से 2026 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है।

भारत में स्वच्छ जलापूर्ति की स्थिति

- 2021 के केंद्रीय बजट में शहरी क्षेत्रों के लिए घोषित सार्वभौमिक जल आपूर्ति योजना केंद्र सरकार की 2019 में लॉंच की गयी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का ही एक भाग है।
- यह मिशन सभी घरों तक नल-जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए देश का 12वां प्रयास है, जिसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इससे पहले के सभी प्रयासों में भारत एक भी वांछित सफलता प्राप्त नहीं की है।
- जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से जुड़े जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत अभी तक केवल लक्षित घरों (6.55 करोड़) में से केवल 34 प्रतिशत घरों तक ही नल-जल की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है।
- अक्टूबर 2019 तक भारत के गांवों में हर घर में शौचालय निर्माण के लिए शुरू किए गए केंद्र के फ्लैगशिप स्वच्छ भारत मिशन को सफल घोषित किया गया है। इसके बाद ग्रामीण भारत में नल के पानी की आपूर्ति

को एक बड़ी आवश्यकता मानते हुए इसे पूरा किए जाने पर बल दिया जाना चाहिये।

- 2012 और 2017 के बीच ग्रामीण जल आपूर्ति की स्थिति का विश्लेषण करने वाली CAG की रिपोर्ट के अनुसार, 4.76 लाख बस्तियां, जहां पूरी तरह से नल-जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी थी, अब वह बस्तियाँ आंशिक नल-जल आपूर्ति के दायरे में वापस आ गयी हैं। जिससे यह पता चलता है कि सिर्फ पहुँच स्थापित कर देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे बनाए रखना भी आवश्यक है।

जल जीवन मिशन के बारे में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी।
- सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिये पानी पहुंचाना है।
- इस मिशन के तहत कृषि में पुन: उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

02

04

06

01 '19 शताब्दी में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में हुए किसान आन्दोलन धार्मिक नहीं थे परन्तु अधिकतर मामलों में धर्म ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई'। इस संदर्भ में 19 शताब्दी में भारत में हुए किसान आन्दोलन की प्रकृति का उल्लेख कीजिए।

02 म्यांमार में हाल ही में हुए तख्तापलट के प्रभावों का विश्लेषण करें। इसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए?

03 व्यापक आर्थिक स्थिरता को स्पष्ट कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 2021 का बजट व्यापक आर्थिक स्थिरता से विचलन प्रस्तुत कर रहा है? टिप्पणी कीजिए।

04 हाल ही में भारत सरकार ने वाशिंगटन सहमति (Washington Consenus) के सिद्धांतों को अपनाने पर बल दिया है। क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक हो सकता है? विश्लेषण कीजिए।

05 हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में COVID-19 के दौरान आय असमानता बढ़ी है। मूल्यांकन करें।

06 'पहाड़ी राज्यों के विकास में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर ही विकास के मार्ग पर बढ़ा जा सकता हैं'। उत्तराखण्ड ग्लेशियर आपदा के संदर्भ में उपरोक्त कथन का परीक्षण कीजिए।

07 भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका को कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए आर्थिक सहायता दी है। भारत का यह पहल क्या भारत-अफ्रीका संबंधों को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा? टिप्पणी करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य

(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

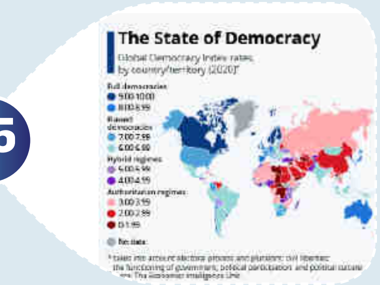

01 'विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021' का विषय क्या है?

आर्द्रभूमि एवं जल

02 किस राज्य में 'हर घर पानी, हर घर सफाई' योजना शुरू किया गया है?

पंजाब

03 किस राज्य में पहला 'ह्यूमन मिल्क बैंक' स्थापित किया गया है?

केरल

04 वर्ष 2020 का 'आक्सफोर्ड हिंदी शब्द' किसे चुना गया है?

आत्मनिर्भरता

05 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा जारी 'डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020' में भारत का रैंक क्या है?

53 वीं

06 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 'भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020' में भारत का रैंक क्या है?

86वीं

07 किस राज्य में देश का पहला 'चक्रवात' परीक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा?

ओडिशा

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01

03

05

01 ‘उच्च शिक्षा वो नहीं जो हमें सिर्फ जानकारी देती है बल्कि वह है जो हमारे जीवन को सफलता का एक नया आयाम देती है’।

रविंद्रनाथ टैगोर

02 एक अन्यायपूर्ण कानून को न मानना एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।

मार्टिन लूथर किंग

03 ‘कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।’

अब्राहिम लिंकन

04 ‘मनुष्य आपनी क्षमता और आत्म विश्वास के साथ, एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकता हैं।

दलाई लामा

05 हर काम को तीन अवस्थाओं से गुजरना होता है–उपहास, विरोध और स्वीकृति।

स्वामी विवेकानंद

06 भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं।

महात्मा गांधी

07 गुलामी बहुत बुरी होती है भले ही इसका नाम कितना भी खूबसूरत क्यों न हो।

मौलाना अबुल कलाम आजाद

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

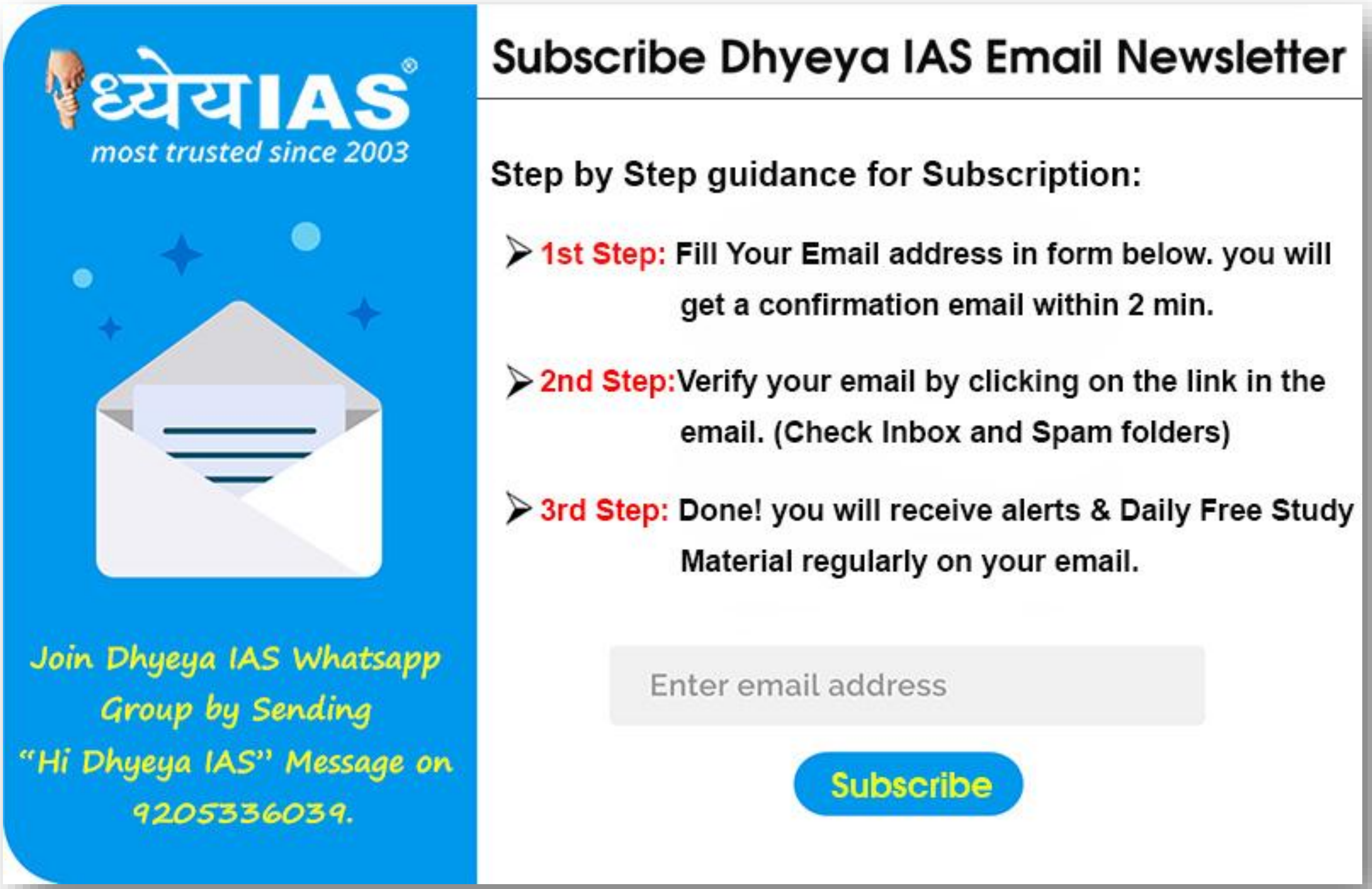

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com